● वर्ष-4
● अंक-122
रायपुर, बुधवार
01 जनवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

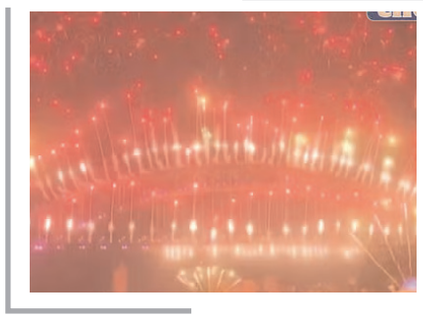

नववर्ष की शुभकामनाएं

आने वाला कल-नई राजनीति वाला हो नया साल

शिव शुक्ला

कोई चैन की सांस लेते हुए पीछे मुड़कर देखे कि वह बेहद विभाजनकारी राजनीति के बीते वर्ष से खुद को कैसे बचा सका, या फिर यह सोचकर बेचैन हो कि क्या वह इस बोझ को 2025 में भी साथ ले जाने वाला है? दरअसल, बेहद कड़वे माहौल में हुए 2024 के आम चुनाव ने देश की राजनीति को इस कदर बांट दिया है कि इसके घाव अब तक ताजा हैं और सभी संकेत यह दर्शा रहे हैं कि इनमें कमी आने के भी कोई आसार नहीं दिखते। साल का अंत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन की दुखद खबर के साथ हो रहा है। डॉ. सिंह को शुभचिंतकों द्वारा श्रद्धांजलि दी ही जा रही थी कि कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि प्रोटोकॉल और मानदंडों के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार कहां किया जाए। राजनीति की विभाजनकारी प्रकृति की कुरूपता बेहद शर्मनाक है।

वर्ष 2024 में भारत के राजनीतिक परिदृश्य में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों ने जगह ली है। 'चार सौ पार' का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा में 240 सीटें हासिल कीं, जो 272 सीटों के बहुमत से काफी कम हैं। चेहरा बचाने वाली बात यह रही कि भाजपा ने चुनाव पूर्व गठबंधन कर तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और वह आसानी से गठबंधन सरकार बनाने में सक्षम थी। लेकिन इसका संदेश स्पष्ट था कि भारत के लोग भाजपा की वापसी चाहते थे, पर नियंत्रण और संतुलन के साथ। नरेंद्र मोदी लौटे और रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।

लेकिन चुनाव के दौरान हमने यह भी होते देखा कि कांग्रेस पार्टी ने देश भर में यह धारणा फैलाई कि देश का संविधान खतरे में है और अगर जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत दे दिया, तो वह इसे बदल देगी। इस संदेश का असर यह हुआ कि लाखों भारतीयों को लगने लगा कि मोदी की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) आरक्षण नीति को खत्म कर सकता है।

इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के तहत विपक्ष, भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने के एजेंडे को रोकने में सफल रहा। कांग्रेस के नेतृत्व वाले

इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीतीं, जो उनकी खुद की उम्मीद से भी परे थीं। 2014 के आम चुनाव में सिर्फ 44 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करने के करीब तक पहुंची और अल्पकालिक तौर पर ही सही, लेकिन भाजपा की छवि को भी काफी हद तक क्षति पहुंचाने में सफल रही।

ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस हारकर भी जीत गई और भाजपा सदमे में है। आम चुनाव के बाद पहले संसद सत्र में कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने आख्यान गढ़ा और लग रहा था कि भाजपा कुछ कमजोर हो गई है। मीडिया भी संशय में दिखी। जून 2024 में देश के राजनीतिक परिदृश्य में कुछ बदलाव हुए। संविधान बचाओ के साथ फिर से उभरे जाति-विरोधी अभियान ने जून में लोकसभा चुनाव पर तो अहम प्रभाव छोड़ा था, लेकिन इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में उसने अलग ही रूप ले लिया। जून में भाजपा को उलटफेर का सामना करना पड़ा था, लेकिन हरियाणा व महाराष्ट्र में बड़ी और निर्णायक जीत दर्ज करते हुए भाजपा ने पलटवार किया, जहां कांग्रेस की जाति आधारित राजनीति काम नहीं आई।

कांग्रेस ने भाजपा को व्याकुल करने और दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए बीआर आंबेडकर को पार्टी का शुभंकर बनाने की रणनीति अपनाई है। ऐसा लगता है कि वे अस्थायी रूप से क्रोनी कैपिटलिज्म थीम से दूर चले गए हैं, जिसका आरोप वे पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी पर लगा रहे थे। संसद का शीतकालीन सत्र उस वक्त और हंगामेदार हो गया, जब सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर आरोप लगाया गया कि वह आंबेडकर, जिनके प्रगतिशील विचारों ने भारतीयों की दो पीढ़ियों को आकार दिया, के प्रति केवल दिखावा करता है, जबकि इनका इतिहास उनके साथ घृणित व्यवहार की ओर इशारा करता है।

इस वर्ष ने यह भी दिखाया कि राज्यों के चुनाव लड़ रहीं सभी राजनीतिक पार्टियों ने आर्थिक लोकलुभावनवाद की राजनीति को अंगीकार किया। भाजपा ने 'रेवड़ी संस्कृति' के अपने आख्यान को दरकिनार कर दिया, जिसका इस्तेमाल उसने अतीत में खासकर आम आदमी पार्टी की आलोचना करने के लिए किया था। इससे राजकोषीय संतुलन को लेकर चिंता बढ़ गई है। इन लोकलुभावन उपायों के कारण महाराष्ट्र ने अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को काफी बढ़ा दिया। कई राज्यों के बजट में मुफ्त की रेवड़ी बांटने के चलते राजस्व व्यय में तेज वृद्धि देखी जा रही है। विश्लेषक राज्य सरकारों को ऐसी योजनाओं के नुकसान के प्रति आगाह कर रहे हैं, जिनकी वजह से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। क्या मोदी सरकार आगामी वर्ष में अपने उस सुधारवादी एजेंडे पर आगे बढ़ेगी, जिसका उसने वर्ष 2024 में वादा किया है। भाजपा कहती है कि समान नागरिक संहिता और एक राष्ट्र-एक चुनाव उसके एजेंडे में हैं। हालांकि 2024 के आम चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के कुछ महीनों बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों ने भाजपा को यह विश्वास दिया है कि सिर्फ तीन महीने में ही वह देश का मूड बदल सकती है।

एक देश-एक चुनाव से मतदाताओं की परेशानी कम करने और खर्च में कटौती, जैसे कई लाभ होंगे। लेकिन क्षेत्रीय दलों को लगता है कि यह क्षेत्रीय मुद्दों को कमजोर कर सकता है और सत्ता को केंद्रीकृत करके भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करेगा। प्रस्ताव के लिए सांविधानिक संशोधन की जरूरत है, जिसके लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में एनडीए के पास नहीं है।

भारत वर्ष 2025 में इस उम्मीद के साथ प्रवेश करने जा रहा है कि नीति निर्माता और सत्ताधारी दल देश को वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के लिए दृढ़संकल्पित हैं। सामाजिक आंदोलन और आर्थिक रणनीतियां साथ मिलकर चलेंगी, जैसा कि भारत यानी इंडिया में हमेशा होता है।

डिजिटल सुधार के लिए केन्द्र से मिली 250 करोड़

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साथ के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए आईटी आधारित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को लागू कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार ने इस डिजिटल सुधार की सराहना करते हुए राज्य को 250 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के रूप में प्रदान की है।

छत्तीसगढ़ राज्य ने केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन के लिए जस्ट इन टाइम (जेआईटी) मॉडल और एसएनए स्पर्श प्रणाली को अपनाया है। यह प्रणाली वित्तीय प्रवाह को कुशल बनाते हुए निधियों के वितरण, ट्रैकिंग और भुगतान को आसान बनाती है। इसके तहत राज्य

सरकार ने केंद्र की निधि को आरबीआई के ई-कुबेर नेटवर्क और राज्य की निधि को वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) के माध्यम से समेकित किया है। इस पहल से निधि के सही समय पर उपयोग और वास्तविक समय में व्यय की रिपोर्टिंग भी सुनिश्चित हुई है।

इस सुधार के तहत स्मार्ट भुगतान एल्गोरिथम का उपयोग किया गया है, जिससे भुगतान ट्रिगर नियमों के आधार पर वास्तविक समय में किया जाता है। इससे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के परिणाम बेहतर हुए हैं। साथ ही, राज्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म और पोर्टल्स का निर्माण कर आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) को बढ़ावा देने के लिए अपने तकनीक आधारित सुधारों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक बनाया है। राज्य की अधोसंरचना परियोजनाओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम को इस प्रोत्साहन राशि से और अधिक मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि तकनीक आधारित सुधार और सुशासन ही छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास का मूलमंत्र है। यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है, बल्कि जनता के प्रति हमारी सरकार के सुशासन के संकल्प का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास न केवल राज्य को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने आईटी के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है, इसी के तहत् केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए राशि जारी करने, वितरित करने एवं निधियों की ट्रैकिंग करने तथा बेहतर नकद प्रबंधन के लिए राज्य शासन द्वारा एसएनए स्पर्श के अंतर्गत जेआईटी मॉडल को अपनाया गया है। इसके माध्यम से केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए नवीन सिस्टम के माध्यम से कार्य किया जा रहा है।

महाकुंभ में 5 रुपए किलो आटा और 6 रुपए किलो चावल के साथ और भी बहुत कुछ

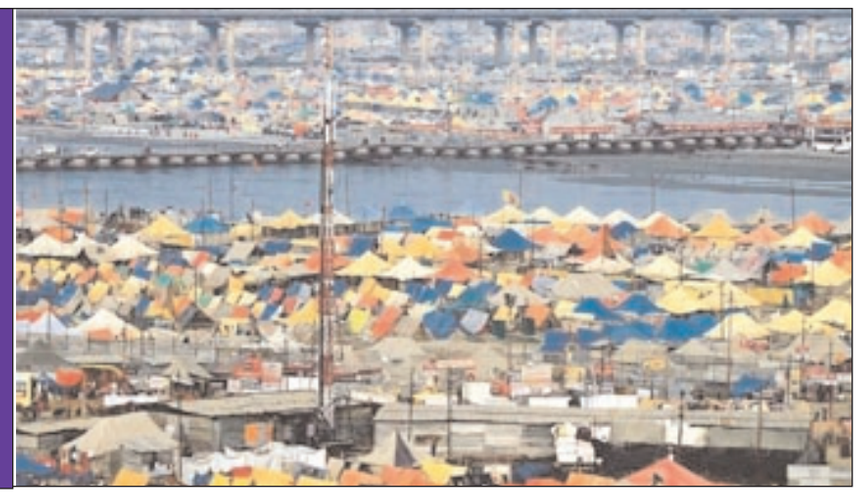

महाकुंभनगर। महाकुंभ में योगी सरकार ने अखाड़ों, संस्थाओं और कल्पवासियों के लिए बड़े पैमाने पर अन्न भंडार की व्यवस्था की है। ऐसा पहली बार है, जब महाकुंभ में इतने बड़े पैमाने पर अखाड़ों, संस्थाओं और कल्पवासियों को नाम मात्र की कीमत पर राशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर अखाड़ों-संस्थाओं और कल्पवासियों को मात्र 5 रुपए में आटा और 6 रुपए में चावल उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। इसके लिए मेला क्षेत्र में 138 उचित मूल्य की दुकानों पर राशन उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार महाकुंभ को दिव्य, भव्य के साथ साथ नव्य रूप देने में लगे हैं। इसके लिए उन्होंने अफसरों को सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख समाचार

आतिशी-संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे संदीप

नई दिल्ली। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच बढ़ते विवाद के बीच नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने मंगलवार को कहा कि वह दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक और नागरिक मानहानि का मामला दायर

करेंगे। यह कदम मतदान से ठीक पहले आतिशी द्वारा दीक्षित पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से धन लेने का आरोप लगाने के आरोपों के जवाब में उठाया गया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि 5-6 दिन पहले दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा था कि मैं बीजेपी से बड़ी रकम ले रही हूं। पिछले 10-12 सालों से उन्होंने कांग्रेस, मुझे और मेरे परिवार को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास पिछले 10-12 वर्षों से आप से पूछने के लिए कई प्रश्न हैं...वह (अरविंद केजरीवाल) शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ 360 पन्नों के सबूत लेकर घूमते थे। बीजेपी के विजय कुमार मल्होत्रा ??ने मुझे बताया कि अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने के बाद बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला और सबूत मांगे।

दिल्ली में नाकामियों से ध्यान हटाने का प्रयास-एलजी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने धार्मिक समिति द्वारा कई धार्मिक संरचनाओं को गिराने के आदेश पर एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था, आपके निर्देश पर और आपकी स्वीकृति से धार्मिक समिति द्वारा दिल्ली भर में कई धार्मिक संरचनाओं को गिराने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गिराए जाने वाले धार्मिक ढांचों की सूची में कई मंदिर और बौद्ध पूजा स्थल शामिल हैं, जो दलित समुदाय द्वारा पूजनीय हैं। इन संरचनाओं को गिराने से इन समुदायों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। दिल्ली के लोगों की ओर से, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि संलग्न सूची में शामिल किसी भी मंदिर और पूजा स्थल को न तोड़ा जाए। सीएम आतिशी के पत्र पर एलजी सचिवालय ने कहा, न तो कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च या कोई अन्य पूजा स्थल तोड़ा या ध्वस्त किया जा रहा है, न ही इस आशय की कोई फाइल आई है। सीएम अपनी और अपने पूर्ववर्ती सीएम की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए सस्ती राजनीति कर रही हैं। एलजी ने पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे उन ताकतों के खिलाफ अतिरिक्त सतर्कता बरतें जो राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर तोड़फोड़ कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री आतिशी ने ग्रंथियों का किया रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को पुजारी-ग्रंथी सम्मान योजना% योजना के तहत ग्रंथियों का पंजीकरण करने के लिए करोल बाग इलाके में संत सुजान सिंह महाराज गुरुद्वारा का दौरा किया। उन्होंने गुरुद्वारे के ग्रंथियों को अपनी पार्टी द्वारा घोषित योजना के लिए पंजीकृत करवाया,

जिसके तहत पुजारियों और ग्रंथियों को मासिक मानदेय दिया जाएगा। उनकी यात्रा उनकी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के एक मंदिर में योजना शुरू करने के कुछ घंटों बाद हो रही है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। ग्रंथी ने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह की सरकार के बाद संभवतः यह पहली सरकार है जो ग्रंथियों के लिए चिंतित है... दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल सरकार बनेगी तो हर मंदिर और गुरुद्वारा के पुजारी को इस योजना के तहत 18,000 रुपये मिलेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन किए।

सत्ता में आए तो जेल जाएंगी ममता, शुभेंदु की चेतावनी

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में एक रैली की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के स्थानीय नेताओं के कथित गलत कामों का विरोध करने वाली संदेशखाली की

महिलाओं पर झूठे आरोप लगाए। शुभेंदु की रैली का आयोजन उसी स्थान पर किया गया था, जहां पर कल एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल होने पहुंची थीं। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो ममता बनर्जी जेल जाएंगी। अधिकारी ने उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 2026 के विधानसभा चुनावों में भाजपा सत्ता में आती है, तो वह एक जांच आयोग गठित करेगी, जो टीएमसी के स्थानीय नेताओं के कथित अत्याचारों की जांच करेगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले संदेशखाली में माताओं-बहनों की गिरफ्तारी की साजिश रची थी। झूठे आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

पाकिस्तान में घरेलू गैस की कमी से मचा हाहाकार

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में अत्यधिक ठंड और सुई गैस आपूर्ति में लगातार रुकावटों के कारण खुले बाजार में कोयला, सूखी लकड़ी, सिलेंडर गैस और केरोसिन समेत वैकल्पिक ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे मध्यम वर्ग को इन बढ़ती लागतों का सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सुई गैस की अनियमित आपूर्ति और कम दबाव के कारण तंदूर और होटलों को वाणिज्यिक गैस सिलेंडर पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिसके कारण एक पूर्ण आकार के सिलेंडर की कीमत बढ़कर 14,000 पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) हो गई है। एक छोटा सिलेंडर 800 पाकिस्तानी रुपये में बेचा जाता है, एक मध्यम सिलेंडर की कीमत 1,500 पाकिस्तानी रुपये है, और केरोसिन तेल की एक बोतल 180 पाकिस्तानी रुपये में बेची जा रही है, जिसे अक्सर बढ़ी हुई कीमतों पर खाली पेय बोतलों में दिया जाता है। सूखी लकड़ी 2,000 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा रही है, जबकि थोड़ी गीली लकड़ी 1,700 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है, उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलोग्राम है, और मध्यम धुएं वाले कोयले की कीमत 130 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलोग्राम है।

2024 में इन द्विपक्षीय संबंध में आया बदलाव

कनाडा-भारत के रिश्तों में खटास, सऊदी-ईरान आ रहे पास

वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। जहां कुछ मामलों में पुराने सहयोगी दुश्मन बनते दिखे, वहीं कुछ मामलों में दोनों देशों के बीच छोटी-छोटी दरारें बढ़ती गईं। कई देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में नाटकीय रूप से बदलाव आया है, जो दर्शाता है कि भू-राजनीतिक परिदृश्य कैसे बदलता रहता है। जहां कुछ लोगों ने दुश्मनी भुलाने और एक-दूसरे के साथ संबंध मजबूत करने का फैसला किया, वहीं कुछ अन्य देशों के बीच संबंध इस हद तक खराब हो गए कि कई लोगों को डर है कि अब वापसी संभव नहीं है। भारत के द्विपक्षीय संबंधों में सबसे बड़ी खटास कनाडा के साथ देखी गई, जहां एक खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी की हत्या एक गहन राजनयिक विवाद के केंद्र में बनी रही।

1. भारत कनाडा के बीच का विवाद पूरे साल छया रहा

भारत और कनाडा के बीच के संबंध अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि, 2024 में दोनों के बीच की खाई और चौड़ी होती नजर आईं। विवाद के केंद्र में 2023 में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला रहा। जिसने दोनों देशों के संबंधों की दिशा बदल दी। निज्जर के निधन के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर कहते दिखे कि निज्जर की हत्या के लिए भारत सरकार के लिए काम करने वाले एजेंट जिम्मेदार हैं। हालांकि भारत ने दावों का खंडन करते हुए इसे बेतुका करार दिया और बदले में ओटावा से सबूत पेश करने के लिए भी कह दिया। इसके कारण अंततः दोनों देशों के कई राजनयिकों को निलंबित कर दिया गया। पूरे विवाद की पटकथा की शुरुआत 2023 से ही शुरू हो गई थी। कनाडाई सरकार ने हिंदू मंदिरों की बर्बरता में वृद्धि और ओटावा में भारतीय राजनयिकों को मिल रही धमकियों से निपटने के लिए कुछ नहीं किया। वर्ष 2024 में पूरे कनाडा में खालिस्तानी समर्थक आंदोलन का उभार हुआ। जबकि भारत सरकार ने इस मामले पर चिंता जताई।

मई 2024 में कनाडाई पुलिस ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर आरोप लगाए। तीनों व्यक्तियों की पहचान करणप्रीत सिंह (28), कमलप्रीत सिंह (22) और करण बराड़ (22) के रूप में हुई। कुछ दिनों बाद अधिकारियों ने मामले में चौथे संदिग्ध को पकड़ लिया। दो महीने बाद एडमॉन्टन में बीएपीएस

स्वामीनारायण मंदिर बर्बरता का शिकार हो गया। भारत ने एक बार फिर खालिस्तानी आंदोलन की हिंसक प्रकृति पर चिंता जताई, लेकिन इस संबंध में बहुत कुछ नहीं किया गया। 15 अक्टूबर को ट्रूडो ने भारतीय एजेंटों पर गुप्त सूचना-एकत्रित करने की तकनीक, कनाडाई लोगों को लक्षित करने वाले जबरदस्ती व्यवहार और धमकी और हिंसक कृत्यों में शामिल होने का आरोप लगाया। कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जोली ने बाद में कहा कि ओटावा में सक्रिय भारतीय राजनयिक निगरानी में हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर चिंता जताई, लेकिन दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ती गईं।

अमेरिका और वेनेजुएला के बीच का विवाद

वर्ष 2024 में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव काफी बढ़ गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से अमेरिका की नाराजगी दुनिया भर में जगजाहिर है। वाशिंगटन ने अक्सर मादुरो के कठोर शासन की आलोचना की है और देश में मानवाधिकारों के दुरुपयोग का आह्वान किया है। इस संबंध में यह वर्ष भी कुछ अलग नहीं था। वर्ष 2024 में अमेरिका-वेनेजुला संबंधों के बिगड़ने में योगदान देने वाले दो कारक थे। गुयाना पर वेनेजुएला की बढ़ती मुखरता और देश के समस्याग्रस्त राष्ट्रपति चुनाव। गौरतलब है कि एस्सेक्विबो क्षेत्र को लेकर वेनेजुएला और गुयाना के बीच लंबे समय से क्षेत्रीय विवाद चल रहा है, जो पिछले साल संकट में बदल गया।

तालिबान का समर्थन करने की कीमत अब चुका रहा पाकिस्तानः जब अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख रशीद अहमद ने अफगानिस्तान के साथ तोरखम क्रॉसिंग पर एक विजयी संवाददाता सम्मेलन दिया। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री इमरान खान ने तालिबान की सत्ता में वापसी की तुलना अफ़गानों द्वारा गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ने से की। तालिबान और पाकिस्तान के बीच प्राचीन काल से मजबूत संबंध रहे हैं। कई तालिबान नेता और लड़ाके पाकिस्तानी इस्लामिक धार्मिक स्कूलों से स्नातक हैं, जिनमें दारुल उलूम हक्कानिया भी शामिल है, जहां तालिबान आंदोलन के संस्थापक मुल्ला मुहम्मद उमर ने अध्ययन किया था। कई लोगों का मानना ??है कि पाकिस्तान के समर्थन और शरण के बिना तालिबान काबुल में फिर से अपनी पकड़ नहीं बना पाता।

अस्थिर मीडिल ईस्ट को स्थिर करेंगे ईरान-सऊदी अरब के रिश्ते : पश्चिम एशिया एक और दूसरे संघर्ष में उलझा हुआ था, ईरान और सऊदी अरब अपनी दशकों पुरानी प्रतिद्वंद्विता को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। 2023 में, दोनों देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

बालोद की घटनाएं जो साल 2024 में चर्चाओं में रही

बालोद। सभी नव वर्ष 2025 के स्वागत को आतुर हैं। नए वर्ष के साथ हम नई उम्मीद संजोए हुए हैं। लेकिन साल 2024 ने हमें क्या दिया और हमसे क्या लिया ये याद रखने की जरूरत है। बालोद जिले में कई ऐसी घटनाएं हुई जो लोगों के जेहन में घर कर गई। आइए जानते हैं साल 2024 की बड़ी घटनाएं

नामकरण संस्कार से लौट रहे परिवार की छीनी खुशियां : 15 दिसंबर को बालोद जिले के चौरहापड़ाव इलाके में कार एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। फिर स्थानीय लोगों की मदद से घंटों मशक्कत की गई। काफी कोशिशों के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। डौंडी में कुम्भकार परिवार के घर छट्ठी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कुछ लोग वापस अपने गांव गुरेदा लौट रहे थे। भानुप्रतापपुर-दल्ली राजहरा मुख्य मार्ग पर डौंडी इलाके के चौरहापड़ाव में उनकी गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई।

धर्मांतरण में पहली बार आत्महत्या : बालोद जिले में दिसंबर महीने में एक आत्महत्या ने पूरे हिंदू समाज को धर्म के प्रति सोचने पर मजबूर कर दिया। अर्जुंदा थाना क्षेत्र के युवक ने थाने में लिखित शिकायत करते हुए लिखा था, %मैं गजेंद्र देवांगन पिता चंद्रशेखर देवांगन जो कि अर्जुन्दा के वार्ड-11 में रहता हूं, मेरी पत्नी राकेश्वरी देवांगन जो कि आए दिन मुझसे वाद विवाद करती है, और बच्चों को छोड़कर बार बार मायके चली जाती है, और वह ईसाई धर्म को अपना चुकी है, जिसको लेकर मुझे आपत्ति है, जिसकी सूचना दे रहा हूं, उसपर उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन कुछ समय बाद उसने आत्महत्या कर ली। कथित तौर पर धर्मांतरण के दबाव को लेकर आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई थी हालांकि पुलिस अब तक मामले की जांच कर रही है।

महिला जनप्रतिनिधि का अपमान: गुरूर नगर पंचायत में एक ऐसा दौर आया जब पहली बार एक महिला जनप्रतिनिधि का अपमान हुआ। गुरूर नगर पंचायत की घटना है। गुरूर नगर पंचायत परिसर को तोड़े जाने को लेकर पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया। ऐसे में एक और वीडियो ने पूरे प्रदेश में हंगामा मचा दिया। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज महिलाओं ने शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड की महिला पार्षद के साथ जमकर मारपीट की है। कुछ महिलाओं ने महिला पार्षद कुंती सिन्हा को घर से खींचते हुए निकाला और सड़क पर ले जाकर पटक दिया। उसी वक्त कुछ सेकंड पहले ही हाईवे से एक ट्रक गुजरा था। यह घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया था।

भाजपा संगठन का हुआ विस्तार: बालोद जिले के सत्ताधारी पार्टी का बरसो बाद अब पुन: परिसीमन हुआ है। जिले के तीन विधानसभा के हिसाब से पहले 9 मंडल हुआ करते थे लेकिन परिसीमन के बाद से यहां पर 17 मंडल अस्तित्व में आया। जहां पहली बार नए मंडल अध्यक्ष बनाए गए।

महिलाओं से लोन स्कैम: पुलिस पूरे जिले भर में साइबर फ्रॉड से बचने अभियान चलाती रही और प्रशासन के नाक के नीचे सैंकड़ों महिलाओं से लोन स्कैम हो गया। जिले के करीब 95 से अधिक गावों की हजारों महिलाएं ठगी का शिकार हो गई। लोन के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी महिलाओं से की गई। किनारगोंदी की 100 से अधिक महिलाओं ने गुरुर थाने में इस मामले की शिकायत की। सप्तऋषि संस्थान के खोलबाहरा नामक व्यक्ति ने एजेंट बनकर गुरुर क्षेत्र की महिलाओं के नाम से 30 हजार से दो लाख रुपये तक का लोन निकाला। महिलाओं को महज तीन से पांच हजार रुपये देकर बाकी लोन के पैसे की किश्त बैंक में जमा करने की बात कहते हुए महिलाओं के साथ ठगी की। शुरुआती आंकड़ों से 70 करोड़ के ठगी की बात सामने आई। जिले की ये सबसे बड़ी ठगी बनकर सामने आई। फिलहाल आरोपी गिरफ्त में है।

कॉम्प्लेक्स विवाद, सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई : बालोद जिले में सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई जिले के गुरूर नगर में देखने को मिली। यहां व्यापारी संघ ने बाजार चौक में 45 से लेकर 50 की संख्या में कॉम्पलेक्स बनाए। जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई। 12 जुलाई की सुबह प्रशासन अपने दस्ते के साथ पहुंचा और बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया।

धान खरीदी केंद्र में बारदाना न होने से भड़के किसान, सड़क पर लगाया जाम

गौरेला पेंड्रा मरवाही। धान खरीदी केंद्र में धान खरीद न होने से धान बेचने आए किसानों ने सड़क पर बैठकर कर घंटों चक्का जाम कर दिया। केंद्र में बारदाने की कमी की वजह से धान की खरीद नहीं होने के कारण धान खरीद बंद की गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन की ओर से एसडीएम मरवाही मौके पर पहुंचे। किसानों को समझाकर जाम खुलवाया और देर रात तक धान की खरीद करने की बात कही, तब कहीं जाकर नाराज किसानों ने चक्का जाम खोला।

धान खरीद खत्म होने में अभी एक महीने का समय शेष है और केंद्रों में अभी से बारदानों की कमी होने लग गई है, जिसकी वजह से किसान उग्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सामने आया मामला मरवाही के लरकेनी समिति के कोदवाही धान खरीदी केंद्र का है, जहां आज किसान सुबह जब अपनी फसल को सहकारी समिति के कोदवाही लेकर सैकड़ों वाहन से पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि केंद्र में तो आज बारदाने ही उपलब्ध नहीं हैं। पहले तो किसान ने बारदाना आने का काफी समय इंतजार किया, पर जब उन्हें लगा कि आज बारदाना आने के साथ-साथ धान बिकना भी मुश्किल है, तब आक्रोशित किसानों ने मुख्य सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया।

सैकड़ों आक्रोशित किसान पेंड्रा सिवनी मरवाही मुख्य मार्ग पर बैठ गए। स्थानीय प्रशासन को जब मामले की जानकारी हुई तो वह मौके पर पहुंचा और धान खरीद करने की मांग की। लगभग तीन घंटे तक किसान सड़क पर मौजूद रहे, तब कहीं जाकर प्रशासन की ओर से एसडीएम मरवाही मौके पर पहुंचे और आक्रोशित किसानों की काफी मान-मनौव्वल की। इसके बाद किसान इस बात पर राजी हुए कि उनके धान की खरीद आज ही की जाएगी। किसान इसके साथ-साथ यह भी मांग कर रहे थे कि फड़ प्रभारी पर भी कार्रवाई की जाए क्योंकि जब बारदाने नहीं थे तो समय पर बारदानों का प्रबंध क्यों नहीं किया गया। किसानों का कहना था कि यदि आज धान खरीद नहीं हुई तो उनके खलिहान से खरीदी केंद्र लाने तक में हुए उनके हजारों रुपये के परिवहन एवं मजदूरी पानी में चली जाएगी। साथ ही उन्हें अगला टोकन लेने में भी परेशानी होगी। इसके बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया कि उनके धान की खरीद आज ही देर रात तक की जाएगी, हालांकि प्रशासन पूरे मामले पर जिम्मेदारी तय करने के साथ-साथ भविष्य में इस तरह के घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने की भी बात कह रहा है।

बलरामपुर रामानुजगंज नपं जहां अध्यक्ष देते हैं पुजारियों को हर महीने हजार रुपये

बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर रामानुजगंज नगर में बीते 10 वर्षों से मंदिर के सभी पुजारीयों को नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल के द्वारा अपनी ओर से प्रत्येक महीने प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। हिंदुओं के आस्था के केंद्र के रूप में स्थापित नगर के सभी 14 मंदिरों के पुजारीयो को प्रत्येक महीने ?1000 का मानदेय प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जा रहा है।

गौरतलब है कि जनवरी 2014 में नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में रमन अग्रवाल के द्वारा पदभार ग्रहण किया गया था। पदभार ग्रहण करने के बाद उनके द्वारा घोषणा की गई थी कि अपने वेतन का एक भी अपने निजी कार्य के लिए उपयोग नहीं करूंगा इसके बाद से उन्होंने अपने पूरे वेतन की राशि को नगर के मंदिरों के पुजारीयों को देने की घोषणा की थी। नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल के द्वारा शासन से मिलने वाली 7400 रुपए की मानदेय राशि में अपने निजी व्यापार से होने वाले आमदनी को मिलाकर नगर के 14 मंदिर के पुजारीयो को प्रत्येक माह ?1000 प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही है। मंदिर के पुजारीयो ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल के द्वारा 2014 से प्रत्येक माह ?1000 हम लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

मां महामाया मंदिर, श्री राम मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, मां गायत्री मंदिर, शिव हनुमान मंदिर वार्ड क्रमांक 5, दुखेश्वर महादेवमंदिर, थाना परिसर शिव मंदिर, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, श्री रानी सती दादी मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री दुर्गा माता मंदिर सीआरपीएफ कैंप।

नगर पंचायत अध्यक्ष को मानदेय के रूप में 7400 प्रत्येक माह मिलता है परंतु नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल के द्वारा वेतन की राशि का कभी भी निजी उपयोग नहीं किया गया। शासन की ओर से मिलने वाली मानदेय की राशि में अपने निजी व्यवसाय से होने वाली आमदनी को मिलाकर मंदिर के पुजारीयो को प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का कार्य किया।

इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष रमन अग्रवाल ने कहा कि मैंने पूर्व में संकल्प लिया था कि निर्वाचन के बाद मंदिर के सभी पुजारीयो को प्रोत्साहन राशि दूंगा। 2014 में जब मैं नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया उसके बाद से ही मैंने अपने पूर्व संकल्प के अनुसार मंदिर के सभी पुजारीयो को प्रोत्साहन राशि देना चालू कर दिया जिससे मंदिरों में अपनी सेवाएं दे रहे पुजारियों को थोड़ी राहत मिल सके। मेरा प्रयास था कि यह राशि बढ़े परंतु अफसोस रहा कि यह राशि मैं नहीं बढ़ा सका।

शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल!

20 साल से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के शिक्षा विभाग में एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। लगभग 20 वर्षों से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे व्यक्ति पर जिला शिक्षा अधिकारी मेहरबान हैं। शिकायत के बावजूद उक्त शिक्षक को प्रमोशन और स्थानांतरण का लाभ वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी डॉ। डीएन मिश्रा ने दिया है। वहीं, शिकायतकर्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सालभर पहले तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने उक्त शिक्षक पर विभागीय जांच की मांग की थी, लेकिन वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी ने इन आदेशों को दबा दिया और उक्त व्यक्ति से सांठगांठ कर हाईकोर्ट से स्टे लाने तक का मौका दिया।

दरअसल, बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड में कमलेश्वर पटेल नामक शिक्षक बीते कई वर्षों से फर्जी अंकसूची के आधार पर नौकरी कर रहा है। इसकी शिकायत भी विभाग में की गई थी। कमलेश्वर पटेल ने अपने सर्विस बुक में 1997 में 12वीं पास होने का उल्लेख किया है, जबकि जिस सर्टिफिकेट का उन्होंने उल्लेख किया है, उसमें सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है।

मामले में तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने उक्त शिक्षक पर विभागीय जांच की मांग की थी। लेकिन वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी डॉ। डीएन मिश्रा ने पूरे मामले पर्दा डालते हुए शिक्षक कमलेश्वर पटेल को निलंबन से बहाल कर रामचंद्रपुर विकासखंड में पदस्थ किया। वहीं चोरी चुपके स्वयं के आदेश का संशोधन कर वाड्रफनगर विकासखंड में भेजा है जबकि उक्त शिक्षक पर विभागीय जांच करना चाहिए था लेकिन मोटी रकम की उगाही और लेनदेन के बाद इतने बड़े प्रकरण को जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दबाया गया है। पूरे प्रकरण में आवेदक गणों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर लेनदेन करके मामले को दबाने का आरोप भी लगाया है।

जब इस पूरे मामले में लल्लूराम डॉट कॉम की टीम जिला शिक्षा अधिकारी डी.एन। मिश्रा से बात की, तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब जिला शिक्षा अधिकारी को उनके अधीनस्थ अधिकारी ने उक्त शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के लिए पत्र लिखा, तो ऐसे पत्रों को क्यों दबाया गया? जाहिर है कि इतने बड़े प्रकरण को दबाने के लिए कुछ न कुछ लाभ जरूर मिला होगा। मामले में प्रार्थी निर्मल पटेल ने बताया कि कमलेश्वर पटेल फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों और पुलिस में की गई थी। मामला पंजीबद्ध हुआ, आरोपी जेल भी गया और निलंबित भी हुआ। लेकिन वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी डी.एन। मिश्रा की मिलीभगत और बड़ी लेन-देन के चलते मामले को दबा दिया गया। उन्होंने गुप्त आदेश निकालकर आरोपी को पुन: नौकरी में भेजा। निर्मल पटेल ने कहा कि वे जहां तक लड़ाई करनी पड़ेगी, करेंगे और आरोपी को सजा दिलाकर रहेंगे। वर्तमान में प्रकरण सेशन कोर्ट रामानुजगंज में चल रहा है।

बच्चों की स्कूल वैन पलटी

बालोद। स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक बच्चे की स्पॉट पर ही डेथ हो गई। घटना में चार बच्चे घायल हुए हैं। सभी घायल बच्चों को बालोद के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बाद में बेहतर इलाज के लिए सभी को धमतरी रेफर कर दिया गया। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है की स्कूल वैन का ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालोद के एडिशनल एसपी अशोक जोशी ने बताया कि जब ड्राइवर को पकड़ा गया तब भी वो शराब के नशे में चूर था। पुलिस ने शराबी ड्राइवर की डॉक्टरी जांच भी कराई है। पुलिस ने बताया कि आगे से ऐसे हादसे नहीं हो इसकी व्यवस्था की जाएगी। वाहन चालकों का अब वेरिफिकेशन किया जाएगा। मृतक छात्र की उम्र 12 साल थी। छात्र कुणाल माता पिता का इकलौता बेटा था। अशोक जोशी ने कहा बच्चों की वैन चला रहा ड्राइवर शराब के नशे में चूर था। हादसे के बाद जब उसे पकड़ा गया तो उस वक्त भी वो नशे में मिला। ड्राइवर को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल कराया गया है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर ही कुणाल ने दम तोड़ दिया था। घायल चार छात्रों को सामुदायिक स्वास्थ केंद्र लाया गया। बाद में उनको अंबिकापुर रेफर किया गया। मृतक छात्र की एक बड़ी बहन है जिसका विवाह हो चुका है। हादसे के बाद परिवार के लोग सदमे में हैं। घटना के वक्त गाड़ी में कुल 14 बच्चे सवार थे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नपं अध्यक्ष के बेटे सहित तीन पर चाकू से हमला

बलौदाबाजार। सोमवार की देर शाम किसी बात को लेकर कसडोल के क्षेत्र के पास नाबालिगों के बीच विवाद हो गया जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे सहित तीन नाबालिग लड़के और एक बालिका पर चाकू से हमला कर फरार हो गए। इस घटना नपं अध्यक्ष के बेटे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के लिए बलौदाबाजार जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ नाबालिग के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद चाकूबाजी की घटना घटित हो गई जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे के साथ तीन नाबालिग लड़के और एक बालिका घायल हो गई। घटना के बाद उन्हें पहले कसडोल के अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे बलौदाबाजार जिला अस्पताल भेज दिया गया है जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद कसडोल पुलिस मौके पर पहुंची।

टोल बचाने के लिए बन जाता था फर्जी पुलिस, गिरफ्तार

दुर्ग। दुर्ग में खुर्सीपार पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो टोल प्लाजा पर टोल बचाने के लिए पुलिस बना जाता था। आरोपी अपनी कार में नीली बत्ती लगाकर घूम रहा था तभी ट्रैफिक पुलिस ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। पुलिस ने आरोपी जितेन्द्र दुबे के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रववाई करते हुए गिरफ्तार किया है। खुर्सीपार थाना प्रभारी अम्बर सिंह भारद्वाज ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक कार में नीली बत्ती और पुलिस लिखकर सड़क में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वाहन को पकड़कर थाने लेकर पहुंची। आरोपी इस वाहन में नीली बत्ती लगाकर सवारी भी ढोता था। आरोपी जितेन्द्र दुबे ने पूछताछ करने पर बताया कि मोबाइल में वर्दी वाला फोटो खींचकर रखा था जिसे टोल प्लाजा में दिखाकर टोल बचाता था। पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश देकर उक्त वाहन के संबंध में आरसीबुक एक मेनपैक सेट, एक काले रंग का बेल्ट,एक अर्मी की टोपी और आधार कार्ड बरामद किया है।

महतारी वंदन योजना का लाभ लेने पंचायत सचिव निलंबित

महासमुंद। महासमुंद में महतारी वंदन योजना का अनुचित लाभ लेने वाले पंचायत सचिव और उसकी शिक्षिका पत्नी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। शिक्षिका नीलम गोस्वामी और सचिव रमाकांत गोस्वामी को निलबिंत कर दिया गया है। ग्राम पंचायत घोड़ारी में पदस्थ सचिव रमाकांत गोस्वामी ने शिक्षिका पत्नी का फार्म भरा था। गलत जानकारी देकर केशवा में पदस्थ शिक्षिका पत्नी नीलम गोस्वामी को योजना का लाभ दिला रहा था। मामला सामने आने पर कलेक्टर ने निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पंचायत सचिव रमाकांत गोस्वामी को भी जिला पंचायत सीईओ ने निलंबित कर दिया है।

गोभी के बाद टमाटर के दाम में आई गिरावट

बलरामपुर रामानुजगंज। सब्जियों के दामों में लगातार गिरावट आ रही है, सोमवार को जहां आठ रुपये किलो टमाटर बिका वही मंगलवार को चार रुपये किलो में खरीदार नहीं मिल रहे थे। टमाटर अच्छे क्वालिटी के होने के बाद भी थोक सब्जी बाजार में आया टमाटर नहीं बिक पाया। वहीं आज गोभी चार रुपये किलो में बिका। कई सब्जी विक्रेता जाते-जाते तीन रुपये किलो टमाटर बेच कर गए। सब्जी की बंपर खेती क्षेत्र में हो रही है दर्जनों गांवों के लोगों के द्वारा सब्जी की खेती की जा रही है। प्रत्येक वर्ष सब्जी उत्पादक किसानों की संख्या बढ़ते जा रही है कई बार किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है लेकिन कभी-कभी बंपर पैदावार के कारण अचानक सब्जी की आवक बढ़ जाने से रेट गिर जा रहा है। गोभी के बाद अब टमाटर के दाम में लगातार गिरावट आने लगी है। मंगलवार को सब्जी बाजार में स्थानीय लोग एक किलो गोभी लेने आए थे लेकिन जब देखा की 50 रुपये में एक बोरा मिल रहा है तो एक बोरा लेकर गए। गोभी को सुखाकर इसका उपयोग सब्जी के रूप में गरमी में करेंगे।

सड़क पर बैठे तीर्थ यात्रियों को ट्रक ने रौंदा

रायपुर। धमतरी का साहू परिवार अमरकंटक की यात्रा कर लौट रहे थे, गाड़ी में तकनीकी खराबी आने के कारण सभी यात्री सिमगा के पास सड़क किनारे बैठे थे कि श्री सीमेंट से सीमेंट लेकर आ रहे ट्रक के चालक ने उन्हें रौंद दिया जिससे घटना स्थल पर ही दो मासूम बच्चों की मौत हो गई वहीं 13 लोग घायल हो गए। गंभीर रुप से घायल कुछ लोगों को रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में भर्ती किया गया वहीं कुछ का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। सिलतरा पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धमतरी का साहू परिवार अमरकंटक की यात्रा से वापस धमतरी जा रहा था। अचानक उनकी गाड़ी में तकनीकी खराबी आ गई। इस बीच परिवार के सभी सदस्य गाड़ी से उतकर सिक्स लाइन वाले सड़क के किनारे बैठे थे। इसी दौरान श्री सीमेंट से सीमेंट लेकर आ रहे ट्रक क्रमांक सीजी 08 एबी 8811 के चालक महेंद्र कुमार ने गाड़ी को सड़क किनारे दौड़ा दिया और तीर्थ यात्रियों को रौंद दिया।

नक्सलवाद पर नकेल का साल रहा 2024? अकेले छत्तीसगढ़ में ही 1000 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

उमेश चतुर्वेदी

बीते वक्त में क्या खोया और क्या पाया, हर नए साल के साथ इसके मूल्यांकन की परंपरा है। इस लिहाज से अगर बीते हुए यानी साल 2024 का मूल्यांकन करेंगे तो कई बिंदुओं पर हमें निराशा हाथ लगेगी तो कई उपलब्धियों और कामयाबियों का भी जिक्र होगा। लाल आतंक के रूप में विख्यात नक्सलवाद पर नकेल बीते हुए साल की उपलब्धि कही जा सकती है। इसका श्रेय निश्चित तौर पर गृहमंत्री अमित शाह को जाता है, लेकिन इसमें भूमिका राज्यों की भी कम नहीं रही है।

बीते साल सुरक्षा बलों की कार्रवाई में भारी संख्या में नक्सली या तो मारे गए हैं या फिर गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही कई नक्सलियों ने समर्पण करके मुख्यधारा की जिंदगी को अपनाया है। नक्सली आतंक पर कामयाबी के पीछे रही तीन-स्तरीय रणनीति, जिसके तहत सबसे पहले नक्सलियों पर समर्पण का दबाव बनाया गया। अगर इसके बावजूद नक्सली नहीं मानता तो उसकी पहले गिरफ्तारी के लिए रणनीति बनाई गई। इसके बावजूद अगर नक्सलवादी नहीं माने तो उनके खिलाफ निर्णायक मुठभेड़ की तैयारी की गई। इसी का असर रहा कि बीते साल अकेले छत्तीसगढ़ राज्य मे ही करीब एक हजार से ज्यादा नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया या फिर उनकी गिरफ्तारी की गई है, जबकि करीब 287 नक्सली मारे गए। इनमें झारखंड में मारे गए नक्सलियों की संख्या सिर्फ नौ रही, जबकि सबसे ज्यादा नक्सली छत्तीसगढ़ में मारे गए। झारखंड में इसी तरह एक सैक मेम्बर, दो जोनल कमांडर, छह सब जोनल कमांडर और छह एरिया कमांडर गिरफ्तार किए गए। इन सभी नक्सलियों पर 36 लाख का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ की कमर सबसे ज्यादा उस छत्तीसगढ़ में टूटती नजर आ रही है, जहां नक्सलियों कभी कांग्रेस के

तकरीबन समूचे राज्य नेतृत्व को खत्म कर दिया था। छत्तीसगढ़ में करीब 867 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

नक्सलवाद के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण नक्सल प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचे की कमी को माना जाता रहा है। नक्सलवाद का समूल नाश करने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार ने सबसे पहले इसी समस्या को खत्म करने पर जोर दिया। इसके तहत केंद्र सरकार ने विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान केंद्रित किया । बस्तर समेत तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के हजारों गांवों को सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा गया। इन गांवों में बुनियादी सहूलियतों को बहाल किया गया। इसकी वजह से इन इलाकों के स्थानीय निवासियों की जिंदगी की कठिनाइयां कम हुईं। इसकी वजह से उन्होंने विकास की धारा को अपनी आंख से देखा और भारतीय राष्ट्र राज्य के बारे में उनकी धारणा बदली। इस धारणा को बदलने के बाद सुरक्षा बलों के लिए नक्सलियों को रोकने के लक्ष्य में बड़ी सफलता मिली। नक्सलियों को लोक समर्थन कम हुआ। इसके साथ ही सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजनाओं की शुरुआत की। इसके तहत 15,000 आवास बनाने का फैसला लिया गया, साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में रोजगार को लेकर विशेष योजनाएं चलाई गईं। इससे न केवल हिंसा में कमी आई , बल्कि स्थानीय लोगों की जिंदगी की दुश्वारियां कम हुईं। इसकी वजह से उन लोगों का मन बदला, जो माओवाद की राह पर नक्सलवादी वैचारिक बहकावे में चल पड़े थे। बुनियादी ढांचा सुधारने, रोजगार की स्थितियां बेहतर बनाने और विकास की धारा को बहाने के बावजूद लंबे समय से नक्सल प्रभावित रहे लोगों के लिए मुख्यधारा में लौटना या मुख्यधारा के प्रति भरोसा बनाना बिना सुरक्षा सुनिश्चित किए संभव नहीं था। सरकार ने इस मोर्चे पर भी काम किया और सुरक्षा बलों की प्रभावी उपस्थिति हर संभव स्तर पर की।

नक्सल प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा सहूलियत को बढ़ावा देने के लिए युद्धस्तर पर कार्यक्रम चलाए गए। पहले इन इलाकों के लिए स्कूल और अस्पताल सपना थे, लेकिन अब हालात बदल रहे है। इसके साथ ही, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना भी की गई है। जहां आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। इससे भी नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों का मन बदला है। स्थानीय समुदायों का सहयोग इस अभियान की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। अमित शाह ने प्रभावित क्षेत्रों में जनता से सीधे संवाद स्थापित किया है। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। स्थानीय सुरक्षा बलों को मजबूत करते हुए उनकी मदद से नक्सलवाद को कमजोर किया गया है। इन प्रयासों ने न केवल जनता का विश्वास जीता है, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और स्थिरता लाने में भी मदद की है। इस बीच नक्सलियों पर गहन निगाह रखने के लिए जहां खुफिया तंत्र को मजबूत बनाया गया, वहीं उनकी निगाहबानी के लिए तकनीक का भी खूब सहारा लिया जा रहा है।

ड्रोन जैसी तमाम तकनीकों के जरिए जहां माओवादियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, वहीं सटीक सूचनाओं के चलते उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में भी आसानी हुई है।

संक्षिप्त समाचार

मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गए है पूर्व सीएम, भाजपा का पलटवार

रायपुर। मोहन भागवत के दौरे के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने के आदेश पर प्रदेश में जमकर सियासत मची है। सोमवार को इस मामले पर प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर निशाना साधा था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा पोस्ट करते हुए लिखा था कि, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं। हालांकि, भाजपा नेताओं पर उनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि वे उनके नाम से भी डरते हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर किस अधिकार से उनका कार्यक्रम जारी कर रहे हैं? डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी किस आधार पर लगाई जा रही है? वही भूपेश बघेल के इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के वनमंत्री केदार कश्यप ने पूर्व सीएम पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार भूपेश बघेल का पीछा नहीं छोड़ रहा। कभी मंत्री, कभी करीबी, कभी निज सचिव घेरे में आते हैं। इससे भूपेश बघेल मानसिक रुप से विक्षिप्त हो चुके है। मोहन भागत आरएसएस के सरसंघचालक है और उन्हें जेड सुरक्षा प्राप्त है। प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा व सुविधा दी जाती है।

नये साल से पहले रायपुर में डबल मर्डर, 6 आरोपी अरेस्ट

रायपुर। नये साल से पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर डबल मर्डर से दहल उठी है। मर्डर की इस वारदात से पूरा शहर हिल गया है। चंगोराभाठा में दो युवकों पर पत्थर से हमला कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। ये वारदात डीडी नगर थाना क्षेत्र की है। मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधितकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। मामले में कार्रवाई न किये जाने पर रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि सचिन बडोले यहां का खंड संयोजक था, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। बताया जाता है कि चंगोराभाठा क्षेत्र में देर रात दो युवकों को लाठी-डंडे से हमला कर पीट-पीटकर मार डाला गया। इतना ही नहीं पुलिस से बेखौफ होकर बदमाशों ने 300 मीटर तक दौड़ाकर पीटा। पुलिस ने बताया कि बीती रात साढ़े दस बजे के बाद कृष्ण यादव और सचिन बडोले शराब पी रहे थे। इस दौरान कुछ युवक मौके पर पहुंचे। किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। फिर दोनों युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। दौड़ा-दौड़ाकर पत्थर से मारा गया। आरोपियों ने लहुलुहान कर कृष्णा यादव और सचिन बडोले को मौत की नींद सुला दी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ऑटो सिग्नलिंग के क्षेत्र में कीर्तिमान

रायपुर । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सिग्नल एण्ड टेलीकॉम विभाग ने ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के क्षेत्र में लगातार तीसरे वर्ष 100 किलोमीटर से अधिक ऑटोमैटिक सिग्नलिंग कमीशनिंग कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर श्री एस. के. सोलंकी के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने सरोना-रायपुर दोहरी लाइन खंड में 6 किलोमीटर अतिरिक्त ऑटोमेटिक सिग्नलिंग स्थापित की । इसमें 3 स्वचालित सिग्नल अप लाइन में और 3 डाउन लाइन में लगाए गए हैं। यह स्वचालित सिग्नलिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आधारित है इस प्रक्रिया के तहत रायपुर स्टेशन के इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पैनल इंटरलॉकिंग में आवश्यक बदलाव किए गए। सटीकता के लिए मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सल काउंटर के 36 डिटेक्शन पॉइंट्स और स्वचालित सिग्नलों की निगरानी के लिए ऑटो और स्टैंडबाय वीडीयू भी लगाए गए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने लगातार तीसरे वर्ष 100 किलोमीटर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग कमीशनिंग का कीर्तिमान पार किया है, जो रेलवे के प्रगतिशील और आधुनिक तकनीकी उपायों का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर ने इस उपलब्धि पर अपनी टीम को बधाई दी और इसे यात्रियों के लिए अधिक संरक्षित और कुशल रेल परिचालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

श्मशान घाट पर कर रहे थे तांत्रिक क्रिया पूर्व सरपंच समेत 4 को ग्रामीणों ने पकड़ा

तखतपुर। छत्तीसगढ़ के तखतपुर थाना क्षेत्र के पुरेना गांव में ग्रामीणों ने तांत्रिक क्रिया करते पूर्व सरपंच सहित चार लोगों को पकड़ा। इस दौरान तांत्रिक समेत पूर्व सरंपच की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई की। फिर सभी को पुलिस के हवाले किया। जानकारी के मुताबिक, बीती रात पूर्व सरपंच गांव के श्मशान घाट पर मछली, अंडा, बकरे का भेजा और देसी शराब रखकर तांत्रिक क्रिया करा रहे थे। इसकी सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सामानों को जब्त कर चार लोगों को तांत्रिक क्रिया करते पकड़ा। इस दौरान मौके से महिला सहित दो लोग फरार होने में कामयाब हो गए। ग्रामीणों ने तांत्रिक सहित पूर्व सरपंच की जमकर धुनाई की। इसके बाद चारों को पुलिस के हवाले किया। इस मामले में थाना प्रभारी देवेश राठौर ने बताया कि बीती रात ग्रामीणों से सूचना मिली कि कुछ लोग श्मशान घाट पर तांत्रिक क्रिया कर रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पेट्रोलिंग टीम को भेजकर चार लोगों को थाने लाया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दाल में कुछ काला है, ईडी की पूछताछ में नहीं पहुंचे लखमा

■ **भाजपा ने पोस्टर जारी कर किया प्रहार**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कथित 2000 करोड़ के शराब घोटाले की आग नए सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर भी नहीं बुझी है। बीते दिनों पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के घर में ईडी की दबीश से राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है। अब पूछताछ के लिए कांग्रेस नेता कवासी लखमा के ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने पर भाजपा ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी करते हुए प्रहार किया है।

भाजपा ने पोस्टर किया जारी

सोशल मीडिया पर भाजपा ने एक पोस्ट जारी किया है। इसमें शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा नहीं पहुंचे पर कहा है कि भूपेश के कुशासन में हुए 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में श्वष्ठ के पूछताछ में बुलाए जाने पर पूर्व आबकारी

मंत्री कवासी लखमा नहीं पहुंचे, उनका श्वष्ठ से बचना ये बताता है कि दाल में बहुत कुछ काला है। मामले में ईडी की पूछताछ में कवासी लखमा सहयोग नहीं कर रहे हैं और मलाई चाटकर खुद को अनपढ़ बता रहे हैं।

बता दें कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के धरमपुरा, रायपुर स्थित बंगले और बेटे हरीश कवासी के सुकमा स्थित घर पर श्वष्ठ ने छापेमारी की थी। यहां दस्तावेज खंगालने के बाद अफसर पूर्व मंत्री की कार को घर से बाहर निकालकर तलाशी ली थी। केवल कवासी लखमा और हरीश लखमा ही नहीं बल्कि कवासी के करीबी सुशील ओझा के चौबे कॉलोनी स्थित निवास और सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी श्वष्ठ ने छापा मारा था। छापेमारी के बाद ईडी की टीम कवासी और उनके बेटे का मोबाइल अपने साथ ले गई थी। सूत्रों के हवाले से अब खबर है कि ईडी ने अपनी श्वष्ठड्ढक्र में दावा किया है कि इस घोटाले में बतौर कमीशन हर महीने 50 लाख रुपए पूर्व मंत्री कवासी लखमा को भी मिलते थे।

रेड के बाद कवासी का बयान

पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने ईडी की कार्रवाई के बाद कहा था कि सुबह से रात तक ईडी की कार्रवाई चलती रही। एक भी कागज निवास से नहीं मिला। अधिकारियों ने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया। अधिकारियों ने जो कागज लाए उसमें दस्तखत करता रहा। अधिकारी ही कागज को पढ़ते लिखते थे, पूरे मामले में अधिकारियों ने गड़बड़ी की है। ईडी का छापा राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस ने विधानसभा में बहुत से मुद्दे उठाए, विधानसभा में जब बड़ा घोटाला को उजागर हुआ, सरकार ने आनन-फानन में दबाव बनाया। भाजपा चुनाव को देखते हुए बदनाम कर राजनीति करने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा था कि एपी त्रिपाठी जैसे अधिकारियों ने मुझको अंधेरे में रखा। मुझे इस घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझसे संपत्ति की जानकारी मांगी है, मैंने समय मांगा है पूरी जानकारी दूंगा। हालांकि अब पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने पर भाजपा ने चोर की दाड़ी में तिनका करार दिया है।

फार्म हाउस पार्टी पर आबकारी विभाग की टेढ़ी नजर

नए साल पर होटल, होटल के बाद रिसॉर्ट और अब फार्म हाउस पार्टी का चलन हो गया है। बदलते ट्रेंड से भली-भांति वाकिफ आबकारी विभाग ने राजधानी के समीप स्थित दो फार्म हाउस और क्लब में छापामार कर बड़े पैमाने पर विदेशी शराब जब्त की। जानकारी के अनुसार, राज्य स्तरीय और रायपुर संभागीय उड़नदस्ता ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 30 दिसंबर को राजधानी के वीआईपी रोड स्थित आदित्य फार्म और भाटागांव स्थित महावीर फार्म में दबिश दी। आदित्य फार्म में ब्लैक लेबल, वोदका, बडवाइजर बियर जब्त किया। महावीर फार्म में 3.250 लीटर शराब और आर्क विला में व्हिस्की जब्त किया गया। तीनों स्थान में मिली सामग्रियों पर छग आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1), 34 (2) ख और 36(ए) के तहत कार्रवाई की गई।

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बड़ी समस्या प्रदेशभर में होगा बड़ा आंदोलन : जूदेव

651 धर्मांतरित परिवारों की घर वापसी, जशपुर से लेकर रायपुर तक निकालेंगे पदयात्रा

रायपुर। 651 धर्मान्तरित परिवारों की सनातन धर्म में घर वापसी को लेकर अखिल भारती घर वापसी के प्रमुख प्रबल प्रताप जूदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा, सक्ती छत में पांव पखारकर 651 धर्मान्तरित परिवारों की पुनः सनातन धर्म में घर वापसी कराया गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा कई वर्षों से सक्ती एवं आसपास के जिलों में धर्म परिवर्तन का विष फैलाया जा रहा है। धर्मान्तरण से चुनाव प्रभावित हो रहा है। पूरे क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल रही है। यह अत्यंत गंभीर और चिंता का विषय है।

अमित जोगी को लेकर प्रबल प्रताप जूदेव ने कहा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनकी स्थिति आप देख रहे हैं। जब वो खुद ही क्रिप्टो क्रिश्चन है वो मेरे पर लांछन लगा रहे हैं। ये काम मेरे पिता ने तब से शुरू किया, जब भाजपा नहीं थी। आप अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, आपका खुद ही आईडेंटी का पता नहीं है। पंजाब के सीएम चन्नी साहब भी हिंदू हैं, लेकिन वो कुछ और काम करते हैं। ये सभी लोग हिंदू समाज को खोखला कर रहे हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध प्रदेशभर में एक बड़ा आंदोलन करूंगा।

जूदेव ने कहा, दूसरी बड़ी समस्या डीलिस्टिंग की है। वनवासी भाई हैं। उन्हें लाभ मिले, इसके लिए मैं बड़ा प्रदर्शन करूंगा।

कुछ धर्मांतरित लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और इसका लाभ भी उठा रहे हैं। डीलिस्टिंग होना बहुत जरूरी है। वनवासी समाज जो कन्वर्ट हो गया है उसका आरक्षण बंद होना चाहिए। इसके लिए जशपुर से लेकर रायपुर तक मैं पदयात्रा

भी करूंगा।

प्रबल प्रताप जूदेव ने कहा, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक समस्या है। खासकर जनजातीय क्षेत्र धर्मांतरण के लिए अतिसंवेदशील हो गया है। ईसाई मिशनरीज भोले-भाले प्रकृति पूजक समाज को भ्रमित कर मतांतरित करा रहे हैं। मिशनरीज धर्म परिवर्तन के लिए प्रोजेक्ट चला रहे हैं। गरीब लोग मतांतरित होकर अपने मूल संस्कृति को छोड़ रहे हैं। उन्हें असभ्य और सनातन धर्म वोरोधी बनाया जा रहा है, जो समाज और देश के लिए खतरनाक है।

जूदेव ने कहा, आज जनजातीय समाज की पहचान पर भी संकट आ गया है। कई गांवों में मूल संस्कृति के साथ जी रहे जनजाति और मतांतरित वर्ग में तनाव देखने को मिल रहे हैं। बस्तर और छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में पिछले वर्ष कई घटनाएं भी हुई थी। छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता था, लेकिन ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मान्तरण के माध्यम से परिवार और समाज को तोड़ा जा रहा है।

सरसंघचालक मोहन भागवत के कार्यक्रम में स्वास्थ्य अमले की तैनाती पर गरमाई सियासत

पीसीसी चीफ बैज ने मंत्री जायसवाल पर साधा निशाना

रायपुर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम में स्वास्थ्य अमले की तैनाती को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि बस्तर से सरगुजा तक स्वास्थ्य के अभाव से आम जनता मर रही है। ऐसे में मोहन भागवत की चापलूसी के लिए स्वास्थ्य विभाग के अमले को झोंक दिया है। इन सब का ज़िम्मेदार कौन है?

बीएड शिक्षकों के हड़ताल को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा में पूर्व शिक्षा मंत्री ने 33 हज़ार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया था। आज शिक्षकों को नौकरी से निकाल रहे। आज प्रदेश भर में कई हजार पद खाली हैं। एक शिक्षक के भरोसे प्रदेश के कई

स्कूल चल रहे हैं। सरकार को इनके आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए। न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए 2827 शिक्षकों का समायोजन करना चाहिए।

इसके साथ ही दीपक बैज ने आरक्षक भर्ती और वन विभाग के भर्ती रद्द करने की मांग सरकार से की है। उन्होंने सरकार के लोगों के साथ मिलीभगत कर हैदराबाद की कंपनी पर गड़बड़ी कर भर्ती करने का आरोप लगाते हुए कहा कि व्यापक पैमाने पर गोलमाल, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पैसे लेकर भर्ती की जा रही है।

उन्होंने कहा कि आरक्षक भर्ती और वन विभाग में भर्ती हैदराबाद की कंपनी कर रही है। हायर्ड कंपनी सरकार के लोगों के साथ मिलकर गड़बड़ी कर रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ सरकार खेल रही है। आरक्षक और वन विभाग की भर्ती तत्काल रद्द हो। इन सबकी जांच कर नए सिरे से भर्तियां की जाए।

कैबिनेट की बैठक में राइस मिलर्स के भुगतान के फ़ैसले पर पीसीसी चीफ ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मिलर्स और सरकार के बीच सिर्फ़ 'ब्रोकर' का कम कर रहे हैं, लेकिन मन और दिल से मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने 15 साल का पैसा दिया है। ये सरकार मिलर्स पर छापा मार रही है।

2024 में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में हासिल की दोहरी कामयाबी, विकास और विश्वास की मजबूत हुई बुनियाद

रायपुर। साल 2024 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा। भाजपा ने बहुआयामी स्तर पर विकास किया। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने दबदबा कायम रखा और साल 2019 के आंकड़े को पार करते हुए कुल 11 सीटों में से 10 सीटों पर कब्जा जमाया। उसके बाद सदस्यता अभियान के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने कमा कर दिया। उसे सदस्यों की संख्या बढ़ाने में भरपूर सफलता हासिल हुई। कुल मिलाकर साल 2024 में बीजेपी छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सफलता के मोर्चे पर लगातार सफल होती चली गई।

23 की कामयाबी 2024 में रही जारी: साल 2024 छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए मजबूत ग्रह गोचर के साथ शुरू हुआ। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सरकार बनाया। 13 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार सत्ता पे काबिज हुई। भाजपा के सत्ता पर काबिज होने के 17 दिन बाद नए साल 2024 ने भी दस्तक दिया। नए साल की नई नीतियों और चुनौतियों के लिए भी छत्तीसगढ़ भाजपा ने खुद को तैयार किया। सरकार बनने के बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हुई। बीजेपी की प्लानिंग को पंख मिले और लोकसभा चुनाव में कामयाबी का डंका बजा दिया।

दिल्ली दरबार में बढ़ी छत्तीसगढ़ भाजपा की शान : लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2019 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 9 सीट मिली थी जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दहाई अंक में जाकर छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों को जीत लिया। भाजपा का दावा सभी 11 सीटों को जीतने का था, लेकिन 10 सीटों पर जीत दर्ज करके भाजपा ने अपने दमदार प्रदर्शन को दिखाया। साल 2024 छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए बहुत सुखद इसलिए रहा कि छत्तीसगढ़ से दिल्ली की बनने वाली सरकार में प्रदेश से सीटों की संख्या भरपूर से ज्यादा थी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के परिणाम ने प्रदेश बीजेपी को इतराने वाले रंग दे दिए। इससे दिल्ली दरबार में छत्तीसगढ़ बीजेपी का कद बढ़ा।

रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जारी रहा बीजेपी का इतिहास : रायपुर दक्षिण उपचुनाव में बीजेपी की जीत का इतिहास जारी रहा। बीजेपी ने 30 साल पुराने परिपाटी वाले इतिहास को बदल दिया। रायपुर दक्षिण सीट से बृजमोहन अग्रवाल 30 साल से काबिज थे। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें उस सीट से हटाकर रायपुर लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव लड़वाया और बृजमोहन अग्रवाल उस सीट पर जीत दर्ज किया और उसे बीजेपी की

झोली में डाला। बृजमोहन अग्रवाल के रायपुर दक्षिण सीट से हट जाने के बाद इस बात की चर्चा जोरों से शुरू हुई थी कि अब रायपुर दक्षिण सीट भाजपा के खाते में रहेगी या नहीं रहेगी। साल 2024 में इस चर्चा पर भी भाजपा ने विराम लगा दिया और भाजपा ने 2024 के रायपुर दक्षिण के लिए हुए विधानसभा के उपचुनाव में मजबूत जीत दर्ज की।

30 साल पुराने इतिहास की परिपाटी बदली : हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट को लेकर बदलाव का ट्रेंड दिखा। यहां से विधायक रहे नेता को बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव लड़वाया। इसके साथ ही बृजमोहन अग्रवाल विधायक से सांसद बन गए। दूसरी तरफ सुनील सोनी साल 2019 में रायपुर से लोकसभा सांसद बने। वह रायपुर दक्षिण उपचुनाव जीतकर विधायक बन गए। भाजपा ने 30 साल पुराने वाले इस इतिहास की परिपाटी को भी 2024 में बदल दिया। एक सीट पर जो नेता वर्षों से विधायक था वह सांसद बन गया और लोकसभा सीट का सांसद विधायक बन गया।

सदस्यता अभियान में बीजेपी को बेहतरीन सफलता: साल 2024 में भाजपा ने सदस्यता अभियान चलाया और उसके लिए 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि जिस रफ्तार से बीजेपी चली थी और जो टास्क भाजपा नेताओं को दिया गया था उसे सभी नेताओं ने बहुत जल्दी ही पूरा कर लिया और उसका यह परिणाम हुआ कि सभी नेताओं को 10व का टास्क सदस्यता अभियान को बढ़ाने का और दे दिया गया। उसके बाद भी भाजपा के नेताओं ने सदस्यता अभियान की उस संख्या को भी पूरा कर लिया जो बीजेपी की एक बड़ी सफलता है। बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़ना प्रदेश में जनता के बढ़ते भरोसे का परिचायक है।

प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कहा 1 साल का वक्त हमारी सरकार को बने हुए हुआ है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के विकास के आंकलन के लिए जो समय रखा था उसमें और क्या करना है यह हो गया है। अब उसे दौड़ना है। सरकार ने जिन नीतियों को बनाया था और जिसे लागू करने का वादा हमने किया था वह सभी योजनाएं धरातल पर उतर चुकी है। जनता को उसका फायदा मिल रहा है।

बोर्ड और निगम अध्यक्ष पद पर नियुक्ति: साल 2024 में बोर्ड और निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर मंथन का दौर जारी रहा। बीजेपी में इस पर चर्चा हो रही है सत्ता और संगठन में भी मंथन जारी है। सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आती रही उसमें बोर्ड निगम के पदों पर अध्यक्षों की बहाली नहीं होना भाजपा की भीतर एक विवाद की वजह जरूर रहा है। अब इस मसले पर बीजेपी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि पार्टी इस पर बड़ा फैसला ले सकती है।

भाजपा में कोई विवाद नहीं : नितिन नबीन ने बीजेपी में विवाद की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में किसी तरह का कोई भी बात नहीं है।आने वाला साल छत्तीसगढ़ के विकास का साल होगा और छत्तीसगढ़ को हर हाल में हम विकास की राह पर ले जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चल रहा है। उनके मार्गदर्शन में चल रही छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार विकास के नए मापदंड पर खड़ी उतरेगी।

7 विशेषज्ञ चिकित्सकों व 35 चिकित्सा अधिकारियों के संविदा नियुक्ति आदेश जारी

■ **स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जारी किया आदेश**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेशानुसार राज्य के रायपुर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 06 चिकित्सा अधिकारियों, बिलासपुर संभाग में 12 चिकित्सा अधिकारियों, सरगुजा संभाग में 05 चिकित्सा अधिकारियों, बस्तर संभाग में 06 चिकित्सा अधिकारियों के साथ दुर्ग संभाग में 06 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा आज इन नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं।

इन डॉक्टरों को संबंधित जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया गया है। नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारी की पदस्थापना से त्वरित इलाज में तेजी आएगी और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञ चिकित्सकों (संविदा) के जारी आदेश में डॉ. अमिताभ लालजी साहू, जिला अस्पताल बेमेतरा, डॉ. क्षमा चोपड़ा, जिला अस्पताल कबीरधाम, डॉ. निकिता खेस, जिला अस्पताल जांजगीर, डॉ. अनु आनी जॉन, जिला अस्पताल मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, डॉ शोएब खान जिला अस्पताल पंडरी रायपुर, डॉ नील माधव गवेल, जिला अस्पताल रायगढ़ व डॉ महिमा निधि जॉर्ज शास. चिकित्सा महाविद्यालय जिला रायगढ़ में पदस्थापना की गई है।

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधिकारी जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

ई-मेलआईडी: cmhobb2019@gmail.com, दूरभाषा नंबर. -07727-223550

क्रमांक/स्वा.वि./निविदा/2024-25/6980 बलौदाबाजार, दिनांक 27/2/2024

//द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना//

सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024-2025 हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) में होने वाले विभिन्न कार्यक्रम हेतु भोजन मिटिंग हॉल/रूम और कैटरिंग, सर्विस स्व सहायता, प्रचार-प्रसार मुद्रण कार्य, मासिक वाहन एवं माल वाहक के लिए पंजीकृत फर्मों से केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से द्वितीय निविदा आमंत्रित किया जाता है। जो निम्नानुसार है:-

क्र.	निविदा प्रकार	विक्रय की प्रारंभ तिथि, समय	विक्रय की अंतिम तिथि, समय	जमा करने की अंतिम तिथि, समय	निविदा खोलने की तिथि, समय
1	भोजन एवं मिटिंग हॉल/रूम कैटरिंग सर्विस स्व सहायता समूह	30-12-2024 Time 10:30 am	20-01-2025 Time 5:30 pm	21-01-2025 Time 12:00 pm	21-01-2025 Time 2:30 pm
2	प्रचार-प्रसार कार्य मुद्रण एवं लेखन कार्य			22-01-2025 Time 12:00 pm	22-01-2025 Time 2:30 pm
3	मासिक वाहन एवं माल वाहक			23-01-2025 Time 12:00 pm	23-01-2025 Time 3:00 pm

निविदा प्रपत्र का क्रय कार्यालयीन दिवस में राशि रु 500/- (पाँच सौ रूपये) का डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक से "District Health Society-Baloda Bazar- NRHM Fund (Main) A/c.- 32273473310" के नाम से बनवाकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के स्टेनो कक्ष से लिया जा सकता है। जो कि वापसी योग्य नही होगा। प्रथम निविदा आमंत्रण में निविदा प्रपत्र ले चुके फर्मों हेतु निःशुल्क प्रपत्र पूर्व के डिमांड ड्राफ्ट दिखाकर प्राप्त कर सकते है।

जी-242504926/1

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

जगहंसाई से बचें नेता

योगेन्द्र योगी

देश में नेताओं की फितरत में शामिल हो चुका है किसी न किसी वजह से विवादों को जन्म देना। इसके लिए किसी का जन्म-मरण भी नहीं देखा जाता। विवादों के चलते राजनीति इतने निचले स्तर पर जा चुकी है कि दिवंगत विभूतियों को भी नहीं बख्शा जाता। इसमें नेताओं का अहम और राजनीति आड़े आ जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह भी इसी राजनीति का शिकार हो गए। सिंह की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि उनके समाधि स्थल को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार और कांग्रेस तथा विपक्षी दल एक-दूसरे को नीचा दिखाने में लग गए। दिल्ली में सिंह के स्मारक के लिए जगह को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। सिंह के स्मारक के मुद्दे पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को देश के महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। राहुल गांधी के मुताबिक आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए यथोचित स्थान उपलब्ध नहीं करा कर सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, उनकी विरासत और खुद्दार सिख समुदाय के साथ न्याय नहीं किया। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने दावा किया कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में असम्मान और कुप्रबंधन देखने को मिला। उन्होंने कहा कि डी.डी. (दूरदर्शन) को छोड़कर किसी भी समाचार एजैंसी को अनुमति नहीं दी गई। डी.डी. ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया। सिंह के परिवार को बमुश्किल ही कवर किया। उन्होंने दावा किया कि सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां सामने की पंक्ति में रखी गईं। कांग्रेस नेताओं, सिंह की बेटियों और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था की खातिर जद्दोजहद करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस महान राजनेता के साथ इस अपमानजनक व्यवहार से सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसकी असंवेदनशीलता उजागर होती है। खेड़ा ने दावा किया कि हैरानी की बात यह रही कि जब भूटान के नरेश खड़े हुए, तो प्रधानमंत्री मोदी खड़े नहीं हुए। अंतिम संस्कार की रस्में निभाने वाले पोतों को चिता तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ा तथा विदेशी राजनयिकों को कहीं और बैठाया गया और वे नजर नहीं आए। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा कैसे पीछे रह सकती थी। यह देखे बगैर कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की भद्द पिटेगी, भाजपा पलटवार करने में पीछे नहीं रही। भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कांग्रेस नेताओं पर प्रहार करते हुए कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस की इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए, कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को जीते-जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, लेकिन अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रही है। इस विवाद में आम आदमी पार्टी ('आप') भी कूद पड़ी। 'आप' के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस विषय को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर किया गया। इसके पूर्व भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाता था। केजरीवाल ने सवाल किया कि सिख समाज से आने वाले और पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और समाधि के लिए भाजपा सरकार 1000 गज जमीन भी न दे सकी?

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां उनका स्मारक भी बन सके। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आबंटित करेगी। आश्चर्य यह है कि अतिविशिष्ट व्यक्तियों के स्मारक के बारे कायदे-कानून का फैसला मनमोहन सिंह की ही सरकार ने वर्ष 2013 में लिया था। इसके मुताबिक दिल्ली में वी.वी.आई.पी. के लिए अलग से कोई स्मारक नहीं होगा तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों जैसे दिवंगत राष्ट्रीय नेताओं के स्मारकों के लिए एक सांझा परिसर बनाने का फैसला किया था।

नई राजनीति वाला हो नया साल

स्मिता प्रकाश

कोई चैन की सांस लेते हुए पीछे मुड़कर देखे कि वह बेहद विभाजनकारी राजनीति के बीते वर्ष से खुद को कैसे बचा सका, या फिर यह सोचकर बेचैन हो कि क्या वह इस बोझ को 2025 में भी साथ ले जाने वाला है? दरअसल, बेहद कड़वे माहौल में हुए 2024 के आम चुनाव ने देश की राजनीति को इस कदर बांट दिया है कि इसके घाव अब तक ताजा हैं और सभी संकेत यह दर्शा रहे हैं कि इनमें कमी आने के भी कोई आसार नहीं दिखते। साल का अंत पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन की दुखद खबर के साथ हो रहा है। डॉ. सिंह को शुभचिंतकों द्वारा श्रद्धांजलि दी ही जा रही थी कि कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि प्रोटोकॉल और मानदंडों के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार कहां किया जाए। राजनीति की विभाजनकारी प्रकृति की कुरूपता बेहद शर्मनाक है।

वर्ष 2024 में भारत के राजनीतिक परिदृश्य में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों ने जगह ली है। 'चार सौ पार' का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा में 240 सीटें हासिल कीं, जो 272 सीटों के बहुमत से काफी कम हैं। चेहरा बचाने वाली बात यह रही कि भाजपा ने चुनाव पूर्व गठबंधन कर तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और वह आसानी से गठबंधन सरकार बनाने में सक्षम थी। लेकिन इसका संदेश स्पष्ट था कि भारत के लोग भाजपा की वापसी चाहते थे, पर नियंत्रण और संतुलन के साथ। नरेंद्र मोदी लौटे और रिकॉर्ड तीसरी बार प्रधानमंत्री बने।

लेकिन चुनाव के दौरान हमने यह भी होते देखा कि कांग्रेस पार्टी ने देश भर में यह धारणा फैलाई कि देश का संविधान खतरे में है और अगर जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत दे दिया, तो वह इसे बदल देगी। इस संदेश का असर यह हुआ कि लाखों भारतीयों को लगने लगा कि मोदी की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) आरक्षण नीति को खत्म कर सकता है।

इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) के तहत विपक्ष, भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने के एजेंडे को रोकने में सफल रहा। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीतीं, जो उनकी खुद की उम्मीद से भी परे थीं। 2014 के आम चुनाव में सिर्फ 44 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करने के करीब तक पहुंची और अल्पकालिक तौर पर ही सही, लेकिन भाजपा की छवि को भी काफी हद तक क्षति पहुंचाने में सफल रही।

ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस हारकर भी जीत गई और भाजपा सदमे में है। आम चुनाव के बाद पहले संसद सत्र में कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने आख्यान गढ़ा और लग रहा था कि भाजपा कुछ कमजोर हो गई है। मीडिया भी संशय में दिखी। जून 2024 में देश के राजनीतिक परिदृश्य में कुछ बदलाव हुए। संविधान बचाओ के साथ फिर से उभरे जाति-विरोधी अभियान ने जून में लोकसभा चुनाव पर तो अहम प्रभाव छोड़ा था, लेकिन इसके बाद अक्तूबर-नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में उसने अलग ही रूप ले लिया। जून में भाजपा को उलटफेर का सामना करना पड़ा था, लेकिन हरियाणा व महाराष्ट्र में बड़ी और निर्णायक जीत दर्ज करते हुए भाजपा ने पलटवार किया, जहां कांग्रेस की जाति आधारित राजनीति काम नहीं आई।

कांग्रेस ने भाजपा को व्याकुल करने और दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए बीआर आंबेडकर को पार्टी का शुभंकर बनाने की रणनीति अपनाई है। ऐसा लगता है कि वे अस्थायी रूप से क्रोनी कैपिटलिज्म थीम से दूर चले गए हैं, जिसका आरोप वे पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी पर लगा रहे थे। संसद का शीतकालीन सत्र उस वक्त और हंगामेदार हो गया, जब सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष पर आरोप लगाया गया कि वह आंबेडकर, जिनके प्रगतिशील विचारों ने भारतीयों की दो पीढ़ियों को आकार दिया, के प्रति केवल दिखावा करता है, जबकि इनका इतिहास उनके साथ घृणित व्यवहार की ओर इशारा करता है।

इस वर्ष ने यह भी दिखाया कि राज्यों के चुनाव लड़ रहीं सभी राजनीतिक पार्टियों ने आर्थिक लोकलुभावनवाद की राजनीति को अंगीकार किया। भाजपा ने 'रेवड़ी संस्कृति' के अपने आख्यान को दरकिनार कर दिया, जिसका इस्तेमाल उसने अतीत में खासकर आम आदमी पार्टी की आलोचना करने के लिए किया था। इससे राजकोषीय संतुलन को लेकर चिंता बढ़ गई है। इन लोकलुभावन उपायों के कारण महाराष्ट्र ने अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को काफी बढ़ा दिया। कई राज्यों के बजट में मुफ्त की रेवड़ी बांटने के चलते राजस्व व्यय में तेज वृद्धि देखी जा रही है। विश्लेषक राज्य सरकारों को ऐसी योजनाओं के नुकसान के प्रति आगाह कर रहे हैं, जिनकी वजह से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। क्या मोदी सरकार आगामी वर्ष में अपने उस सुधारवादी एजेंडे पर आगे बढ़ेगी, जिसका उसने वर्ष 2024 में वादा किया है। भाजपा कहती है कि समान नागरिक संहिता और एक राष्ट्र-एक चुनाव उसके एजेंडे में हैं। हालांकि 2024 के आम चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के कुछ महीनों बाद हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों ने भाजपा को यह विश्वास दिया है कि सिर्फ तीन महीने में ही वह देश का मूड बदल सकती है।

एक देश-एक चुनाव से मतदाताओं की परेशानी कम करने और खर्च में कटौती, जैसे कई लाभ होंगे। लेकिन क्षेत्रीय दलों को लगता है कि यह क्षेत्रीय मुद्दों को कमजोर कर सकता है और सत्ता को केंद्रीकृत करके भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करेगा। प्रस्ताव के लिए सांविधानिक संशोधन की जरूरत है, जिसके लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान में एनडीए के पास नहीं है। भारत वर्ष 2025 में इस उम्मीद के साथ प्रवेश करने जा रहा है कि नीति निर्माता और सत्ताधारी दल देश को वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने के लिए दृढ़संकल्पित हैं। सामाजिक आंदोलन और आर्थिक रणनीतियां साथ मिलकर चलेंगी, जैसा कि भारत यानी इंडिया में हमेशा होता है।

एकात्मता के स्वर — जगन्नाथपुरी

गंगासागर तट पर ओडीसा राज्य में पावन तीर्थ जगन्नाथपुरी स्थित है। इस पवित्र स्थान की गिनती पावन चार धामों व इक्यावन शक्तिपीठों में की जाती है। यह शैव, वैष्णव व बौद्ध मत के भक्तों का श्रद्धा केन्द्र है। सृष्टि के आदि में यज्ञ और वेदाध्ययन की प्रवृति यहीं से होती है। वहाँ के निवासी वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। इस क्षेत्र को अठ्ठारह विद्याओं की निधि कहा गया है। पृथ्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु यहाँ अलभ्य नहीं है। यहाँ पर प्रमुख रूप से भगवान् जगन्नाथ का मंदिर है जिसे ब्रह्मा जी की पाँचवीं पीढी में पैदा हुए सूर्यवंशी महाराजा इन्द्रद्युम्न ने बनवाया था जो मालवा में अवन्ति के राजा थे। पूर्व में यहाँ पर मूर्ति इन्द्र नीलमणि के प्रस्तर की थी। राजा ने विष्णु के रोम से पैदा हुए वृक्ष की लकडी से चार प्रतिमाएँ भगवान् जगन्नाथ, बलराम जी, सुभद्रा व सुदर्शन चक्र की बनवायीं व भव्य मंदिर बनाकर प्रतिमाएँ स्थापित की। यह क्षेत्र पाँच कोश में फैला नीलांचल पर्वत पर समुद्र के किनारे बसा हुआ है। वर्तमान में जो मंदिर दिखाई दे रहा है वह गंगवंशीय राजा अनंग भीमदेव ने बारहवीं सदी में बनवाया था। मराठों ने भगवान् जगन्नाथ के मंदिर की व्यवस्था के लिए वार्षिक सत्ताईस हजार रूपये की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की। प्रतिवर्ष धूमधाम के साथ मूर्तियाँ रथ में रखी जाती हैं। वह रथ दस दिनों तक समुद्र तट पर स्थित मौसी जी के मंदिर तक जाता है।

मूर्तियाँ वहीं रखी जाती हैं। इस रथ को श्रद्धालु आगे खींचते हैं। यहीं से अठारह किलोमीटर दूर साक्षी गोपाल का मंदिर है इसके दर्शन के बिना जगन्नाथपुरी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसी पुरी में आद्यशंकराचार्य जी ने गोवर्धन पीठ की स्थापना की है। यहाँ पर कबीरदास जी ने भी यात्रा की; तो पूर्व हुए रामानुजाचार्य व रामानन्दाचार्य ने भी यहाँ की यात्रायें कीं। मलूकदास व संत चैतन्य महाप्रभुजी यहाँ पधारे। जगन्नाथ का भात, जगत पसारे हाथ, पूछे जात न पात।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

(गतांक से आगे...)

(10) व्यास जी के बनाये हुये वेदान्तसूत्र, मीमांसा की व्याख्या, और योगदर्शन-भाष्य आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। उक्त ग्रन्थों में धर्म का जो विशुद्ध रूप वर्णित किया है, वह भी सब को विदित है, परन्तु पुराणों में उक्त ग्रन्थों के सर्वथा विपरीत बातें दर्ज हैं। इसलिए वेदान्तदर्शन जैसे विज्ञानपूर्ण ग्रन्थ का निर्माता व्यास पुराणों जैसी लचर कृति का कर्ता नहीं हो सकता।

(11) प्रतिवादी ने इस आक्षेप में व्यास जी के बनाए हुये बेदान्तसूत्र आदि ग्रन्थों, और पुराणों में परस्पर विरुद्धता का उल्लेख किया है और इसी कारण के आधार पर पुराणों का व्यासकृत न होना बताया है। परन्तु उन्होंने वेदान्तसूत्रादि के किस सिद्धान्त के प्रतिकूल किस पुराण में क्या लिखा है यह दिखाने का साहस नहीं किया । आर्ष-पद्धति के अनुसार हेतु और दृष्टान्तों के बिना प्रतिज्ञा-मात्र करने से कोई सिद्धान्त स्थिर नहीं हो सकता। यों तो हम भी कह सकते हैं कि आर्यसमाज के समस्त ग्रन्थ वेदों के सर्वथा विपरीत हैं। क्या हमारा एतावन्मात्र कहना समाज को पर्याप्त होगा? इसलिए जब तक कोई समाजी व्यास जी के रचे हुये वेदान्तसूत्रादि ग्रन्थों के साथ पुराणों के किसी सिद्धान्त पर तुलनात्मक विचार करके उसे उनके प्रतिकूल सिद्ध न करदे, तब तक इस प्रकार के आक्षेप का मूल्य कानी कौड़ी भी नहीं ठहर सकता?

यद्यपि उपर्युक्त आक्षेप के उत्तर में जो कुछ कहा गया है, वह पर्याप्त से भी अधिक है, तथापि हम सामान्यत: यह बता देना चाहते हैं, कि वेदान्तसूत्रादि ग्रन्थों और पुराणों में नीचे लिखे सिद्धान्त प्राय: समान रूप से वर्णित हैं; यथा:- (1) उत्तरायण और दक्षिणायन सार्ग, तथा याम्य गति। (2) याज्ञिक प्रक्रिया का फल। (3) विग्रह्वती देवताओं की लोकोत्तर शक्ति।

क्रमश: ...

डीआरडीओ दिवस

मोहम्मद समीर

आज डीआरडीओ का 67वां स्थापना दिवस है। डीआरडीओ का गठन 1958 में भारतीय सेना के पहले से चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय को मिला कर किया गया था। मौजूदा समय में डीआरडीओ के पास पांच हजार वैज्ञानिक हैं। इसके साथ ही इसके पास करीब 30 हजार कर्मी भी हैं।

इसकी स्थापना विश्व स्तरीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्थापित करके भारत को समृद्ध और हमारी रक्षा सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रणालियों और समाधानों से लैस करके निर्णायक बढ़त प्रदान करने के लिए की गई थी। रक्षा क्षेत्र में इसके योगदान के मद्देनजर कहा जा सकता है कि ये अपने स्थापना के उद्देश्य को चरितार्थ करता है।

डीआरडीओ अपने स्थापना के समय 10 प्रतिष्ठानों या प्रयोगशालाओं वाला एक छोटा संगठन था। धीरे-धीरे यह हर मामले में आगे बढ़ा है चाहे वो विषयों की विविधता हो प्रयोगशालाओं की संख्या हो या इसकी उपलब्धियां हों।

डीआरडीओ का काम हमारी रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सेंसर, हथियार, उपकरणों का डिजाइन, विकास और उत्पादन करना व इसके लिए शोध करना है।

यह वैमानिकी, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, लड़ाकू वाहन, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, विशेष सामग्री, नौसेना प्रणाली, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली मिसाइलों, आयुध, प्रकाश का मुकाबला करने वाले विमान, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली जैसे अहम विषयों पर काम करती है।

इसका मुख्यालय दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के निकट ही, सेना भवन के सामने डीआरडीओ भवन में स्थित है। इसकी एक प्रयोगशाला महात्मा गाँधी मार्ग पर उत्तर पश्चिमी दिल्ली में स्थित है। संगठन का नेतृत्व रक्षा मंत्री, भारत सरकार, जो रक्षा मंत्रालय में सामान्य अनुसंधान और विकास के निदेशक तथा रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग (डीडीआर व डी) के सचिव भी हैं, के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा किया जाता है। मुख्यालय स्तर पर, उनकी सहायता अनुसंधान एवं विकास (सीसीआर व डी), प्रौद्योगिकी और निगमित निदेशालय के मुख्य नियंत्रक द्वारा की जाती है। निगमित निदेशालय के अधिकारी, वित्तीय और संपदा प्रशिक्षण, नागरिक कार्य और संपदा, राज भाषा, विजिलेंस, इत्यादि के क्षेत्र/कार्य को तय करते हैं तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला निदेशालय तथा मुख्य नियंत्रक तथा वैज्ञानिक सलाहकार से आरएम के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करते हैं। अतिरिक्त वित्तीय सलाहकार संगठन के उद्देश्यों के मुताबिक धनराशि की उचित उपयोगिता पर संगठन को परामर्श देता है।

ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध निर्माण की चीनी चाल?

प्रमोद भार्गव

चीन ने भारत के साथ मधुर संबंध बनाने के बीच एक नई विस्तारवादी चाल चल दी। उसने भारतीय सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को बनाने की स्वीकृति दे दी है। इस बांध परियोजना को दुनिया की सबसे बड़ी बांध संरचना परियोजना बताया जा रहा है। इसकी लागत का अनुमान 137 अरब अमेरिकी डॉलर है। यह जानकारी चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अधिकारी ने देते हुए कहा है कि 'चीन सरकार ने यारलुंग जांग्बो नदी (ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बती नाम) के निचले क्षेत्रों में एक जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। यह बांध हिमालय की एक विशाल घाटी में बनाया जाएगा। यहां ब्रह्मपुत्र नदी एक बड़ा मोड़ लेती हुई अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में बहती है।

यह समाचार हांगकांग से प्रकाशित होने वाले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपा है। भारत के प्रति चीन का आचरण हमेशा ही संदिग्ध रहा है। चीन इस नाते अपने हितों और विकास के लिए जो भी निर्णय लेता है, वे सीमाई देशों के लिए संकट का सबब बन जाते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की उसकी मंशा ने भारत और बांग्लादेश की चिंता बढ़ा दी है।

बताया जा रहा है कि बांध में भरे पानी से चीन प्रतिवर्ष 300 अरब किलोवाट प्रतिघंटे बिजली पैदा करेगा। सिंचाई के लिए भी यह जल उपयोग में लाया जाएगा। इसके पहले से भी चीन ब्रह्मपुत्र के मूल उद्गम स्थल यारलुंग जांग्बो नदी पर 60 हजार मेगावाट क्षमता का जल विद्युत संयंत्र लगा रहा है।

इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह विशालकाय बांध के निर्माण में लगा है।

आशंका है कि चीन इस बांध में भरे जाने वाले जल का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध जलयुद्ध के रूप में कर सकता है। इसकी काट के लिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग क्षेत्र में 11,200 मेगावाट क्षमता की पनबिजली परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। 1.10 लाख करोड़ रुपए की इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (पीएफआर) भी बन गई है।

एक अन्य 9,380 मेगावाट क्षमता की पनबिजली परियोजना अरुणाचल में पहले से ही निर्माणाधीन है। इस पहल से चीन शिनजियांग के रेगिस्तानी इलाके को उपजाऊ भूमि में बदलना और इस क्षेत्र की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराना चाहता है। दक्षिणी तिब्बत की यारलुंग जांग्बो नदी के जल प्रवाह को रेगिस्तान की ओर मोड़ा जाएगा।

इसे मोड़ने के लिए चीन के अभियंता ऐसी तकनीकों के परीक्षण में जुटे हैं, जिनका प्रयोग कर ब्रह्मपुत्र नदी के जलप्रवाह को 1000 किमी लंबी सुरंग बनाकर मोड़ दिया जाए। इस योजना के जरिये चीन की मंशा अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे तिब्बत से शिनजियांग में पानी ले जाने की है। इससे भारत सरकार के साथ दुनिया भर के पर्यावरण प्रेमी चिंतित हुए थे, क्योंकि सुरंग खुदाई से हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन चीन ने अपने रुख में बदलाव नहीं किया। ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को लेकर चीन का भारत से ही नहीं बांग्लादेश से भी विवाद है।

इस नदी पर कई बांध बनाकर चीन ने ऐसे जल प्रबंध कर लिए हैं कि वह जब चाहे तब भारत और बांग्लादेश में पानी के प्रवाह को रोक दे और जब चाहे तब ज्यादा पानी छोड़कर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दे। चीन ने ऐसी हरकत करते हुए साल 2016 में भारत में जलापूर्ति करने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी जियाबुकू का पानी रोक भी दिया था।

चीन यदि बांधों से ज्यादा पानी छोड़ देता है तो इससे पूर्वोत्तर भारत की कृषि व्यवस्था तहस-नहस हो सकती है। एशिया की सबसे लंबी इस नदी की लंबाई 2900 किमी है। इसी की सहायक नदी जियाबुकू है, जिस पर चीन हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है। दुनिया की सबसे लंबी नदियों में 29वां स्थान रखने वाली ब्रह्मपुत्र 1625 किमी तिब्बत क्षेत्र में बहती है। इसके बाद 918 किमी भारत और 363 किमी की लंबाई में बांग्लादेश में बहती है। समुद्री तट से 3300 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बती क्षेत्र में बहने वाली इस नदी पर चीन 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत तीन पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव पहले ही मंजूर कर चुका है और अब नए बांध निर्माण को मंजूरी दे दी है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पानी के उपयोग को लेकर कई संधियां हुई हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र की पानी के उपभोग को लेकर 1997 में हुई संधि के प्रस्ताव पर अमल किया जाता है। इस संधि के प्रारूप में प्रावधान है कि जब कोई नदी दो या इससे ज्यादा देशों में बहती है तो जिन देशों में इसका प्रवाह है, वहां उसके पानी पर उस देश का समान अधिकार होगा।

इस लिहाज से चीन को सोची-समझी रणनीति के तहत पानी रोकने या उसकी धारा बदलने का अधिकार है ही नहीं। लेकिन चीन संयुक्त राष्ट्र की इस संधि की शर्तों को मानने के लिए इसलिए बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि इस संधि पर अब तक चीन ने हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं। 2013 में एक अंतरमंत्रालय विशेष समूह गठित किया गया था।

इसमें भारत के साथ चीन का यह समझौता हुआ था कि चीन पारदर्शिता अपनाते हुए पानी के प्रवाह से संबंधित आंकड़ों को साझा करेगा। लेकिन चीन ने इस समझौते का पालन नहीं किया जबकि चीन अपने पड़ोसी देश लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम से मेकांग नदी पर बने बांधों के आंकड़े साझा करता है। इस नदी पर चीन ने 11 बांध बना लिए हैं।

चीन जब चाहे तब ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देता है, अथवा इकट्ठा छोड़ देता है। अरुणाचल में जो बाढ़ें आई हैं, उनकी पृष्ठभूमि में चीन द्वारा बिना किसी सूचना के पानी छोड़ा जाना रहा है। अतएव इस नए बांध के निर्माण के बाद यदि चीन के साथ गलवान और डोकलाम की तरह भू-राजनीतिक विवाद उत्पन्न होता है तो चीन इस बांध के जल को नियंत्रित या अधिक मात्रा में छोड़कर भारत के हितों को प्रभावित कर सकता है।

आज का इतिहास

1847 नेथ के हार्लेम के वर्तमान अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया।
1849 फ्रांस ने सीरस नाम से देश का पहला डाक टिकट जारी किया।
1852 नीदरलैंड डाक टिकट जारी करना शुरू किया।
1858 कनाडा ने मुद्रा प्रणाली का प्रयोग शुरू किया।
1873 जापान ने ग्रेगोरीयन कैलेंडर को अपनाया।
1876 बास ब्रूएरी रेड त्रिभुज दुनिया का पहला पंजीकृत ट्रेडमार्क प्रतीक बनाया गया।
1891 वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान जर्मनी में शुरू किया गया।
1892 न्यूयॉर्क हार्बर में एलिस द्वीप पर आव्रजन स्टेशन, अपने अस्तित्व के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारह मिलियन आप्रवासियों को संसाधित करता है।
1894 दक्षिण अफ्रीका का एमेच्योर एथलेटिक संघ जोहानसबर्ग में स्थापित किया गया।
1913 ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर को फिल्मों को वर्गीकृत करने और सेंसर करने का अधिकार प्राप्त हुआ।
1919 एडसेल फोर्ड ने अपने पिता को फोर्ड मोटर कंपनी के प्रमुख का दर्जा दिया।
1925 नॉर्वे की राजधानी क्रिस्टियानिया को पुराना नाम ओस्लो से जाना गया।
1928 अमेरिका में पहला एयर कंडीशंड कार्यालय सेन एंतोनियो में खुला।
1945 द्वितीय विश्व युद्ध : जर्मन लूफ्टवाफे ने निचले देशों में मित्र देशों की वायु सेनाओं को अपंग करने के प्रयास में ऑपरेशन बोडेनप्लेट को लॉन्च किया।
1948 न्यूजर्सी का नवीनतम संविधान लागू हुआ।
1955 भूटान ने पहला डाक टिकट जारी किया गया।
1971 टेलीविजन पर सिगरेट विज्ञापनों का प्रसारण प्रतिबंध लगाया गया।
1979 संयुक्त राज्य अमेरिका और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए।
1986 फ्लेवोलैंड प्रांत नीदरलैंड में स्थापित है।

नए साल का आगाज करती नई आशाएं

डॉ. नाज परवीन

उम्मीदों के गुलदस्ते से लबरेज आने वाला साल %2025% का आगाज पूरी कायनात में जल्द ही हो जाएगा। आने वाले साल के लिए लोगों ने नए-नए संकल्प लगभग तैयार कर लिए होंगे। कुछ तो उनके अमल में लाने की तैयारियों में भी शामिल हो चुके होंगे। बीते कुछ सालों में जिन तकलीफों को दुनिया ने बर्दाश्त किया है, उससे उभरते हुए 2024 की विदाई की तैयारियां अब पूरी होने को हैं। तकलीफों और परेशानियों में जिस तरह से दुनिया में अनगिनत लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया वह यकीनन काबिले तारीफ है।

अब भी लगता है कि दुनिया में फरिश्तों का हुजूम मौजूद है! इस कायनात के इंसानी बाशिन्दों ने अपनी रहनुमाई से साबित कर दिया है। नेकी अभी कायम है और इंसानियत अभी जिन्दा है! ऐसी अनेक मिसालें इतिहास की गवाह बन चुकी हैं। लोगों में बची हुई इंसानियत, मोहब्बत और अपनेपन के जज्बे को देख लगता है दुनिया यकीनन अभी भी बहुत खूबसूरत है। अच्छाई हर शख्स के भीतर मौजूद है। बस उसे हिम्मत से उभारने की जरूरत है।

महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, सूफियां और सन्तों की इस सरजमीं को खुशियों के गुलिश्ता में तब्दील करने का जिम्मा हम भारतीयों का ही है। नया साल इन्हीं उम्मीदों के साथ दस्तक देने को तैयार है। चलो इस कायनात में हर जगह नन्हीं कोपले लगाते हैं, यह चमन है हमारा इसे प्यार से सजाते हैं।

दिसंबर का जिम्मेदार महीना साल भर का लेखा-जोखा जनवरी को सौंपने के लिए सर्दी की बर्फीली मुस्कुराहट के साथ-साथ जनवरी का पूरी गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए तैयार है। साथ ही ऐसा मालूम होता है जैसे जनवरी को जिम्मेदारियों की ताकीद भी सौप रहा हो मानो कह रहा हो कि अच्छे से रखना सब.....पूरा व्यवस्थित, जैसा मैने सौपा है वैसे ही आने वाले साल को सौपना। इत्मेनान और सुकून की विदाई चाहता दिसंबर, मुझे हमेशा परिवार के बुर्जुग सा नजर आता है जो आने वाली पीढ़ियों को नई जिम्मेदारियों को सौपते वक्त विश्वास और भरोसा का चेक साइन करवाकर अपने पास रख लेना चाहत हो। मानों हम से कह रहे हों कि आने वाली पीढ़ियों को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी पीढ़ी की है।

नए साल की एक खासियत यह भी है कि उसके पास सबके लिए अपार संभावनाएं मौजूद रहती है हम अपने संकल्पों के जरिए उन पर अमल करके न केवल अपने जीवन में बल्कि दूसरों की जिन्दगी में भी सकारात्मकता का दीपक जला सकते हैं। एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। खुली आंखों से सपनों को देखें या फिर आंखें बंद करके, सपने तभी सच होंगे जब हम उन्हें पूरा करने की कोशिशों में अपने मौजूदा समय को गवाएगें।

'मेहनत' से सब कुछ बनाया जा सकता है फिर वो तस्वीर हो या तकदीर। सपनों को मेहनत और विश्वास का साथ मिल जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। नए साल का आगाज हमें इन्हीं सम्भावनाओं की ओर लेकर जाने की ताकीद है। कुछ बड़ा करने के लिए हमें मेहनत की फेहरिश्त बडी करनी होगी। तभी सपनें सच होगें उनमें जान भी होगी और ऊंची उड़ान भी।

आने वाला साल भी यकीनन युवाओं का ही है। तकनीकी और विकास की बुलेट ट्रेन किसी भी देश के युवाओं की मेहनत पर ही रफतार पकड़ सकती है। भविष्य को संभावनाओं से भरने में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। भारत तो युवाओं का देश है यदि इन युवाओं की सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा प्राप्त हो जाए तो भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता।

नए साल के संकल्पों में हमें एक वादा पृथ्वी से भी करना होगा कि हम पर्यावरण की सुरक्षा और रक्षा करने की जिम्मेदारी निभाएगें। दिल्ली के आस-पास की जहरीली हवा पहले दिल्ली अब एनसीआर और जल्द ही आगे का रूख इख्तेयार कर लेगी। आज से 100 साल पहले अगर हम किसी से पीने का पानी बेचने की बात करते तो यकीनन वो हमें ऐसा कहने पर गुनहगार का तमगा थमा देता। किसी प्यासे की प्यास बुझाना सबसे बड़ी नेकी कमाने का जरिया हुआ करता था। साफ पानी की पहुंच हर एक तक थी।

नदी, तालाब और कुओं का पानी इतना साफ और मीठा होता था कि फिल्टर पानी की कल्पना करना दूर-दूर तक ख्याली कल्पना भी न थी। जैसे-जैसे हमारी आधुनिकतावादी समझदार पीढ़ी आगे बढ़ी पर्यावरण को दूषित और दूषित करने का काम करने की जद्दोजहद में लग गई। साथ ही इसका ठीकरा एक दूसरे के ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया। कभी-कभी लगता है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब लोग मिनरल वॉटर के साथ-साथ ऑक्सीजन सिलेण्डर भी लेकर बाहर निकलेंगे। क्यों न नए साल में एक वादा पर्यावरण की सांसें लौटाने का भी किया जाए? आखिर ये हवा वापस हमारे पास ही तो आने वाली है।

आने वाला साल निश्चित ही सबके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है। बस जरूरत है तो धैर्य, साहस और ठेर सारी मेहनत की। बीते साल की कुछ घटनाएं मन को बेचैन करने वाली रहीं। जहां कोरोने ने लाख मिन्नतें करने के बावजूद जिंदगियां नहीं बख्शी। मौत के पंजों ने अनगिनत घोसलों को वीरान कर दिया। सांसें अनमोल हैं, यह सबको समझाया।

जाते-जाते भी कभी बदलते वायरस के नामों से कभी पुरानी बीमारियों में नई दहशत के साथ कई चेहरों की मुस्कुराहट हमेंशा के लिए छीन बताया की स्वस्थ शरीर कुदरत का बख्शा नायाब तोहफा है। इसे पूरी जिम्मेदारी से संभालने की आवश्यकता है। फिर भी 2024 के कुछ हताश, निराशा भरे आत्महत्या के कदम मन को दहलाने वाले रहे।

जीवन यूं समाप्त करने का नाम नहीं बल्कि भविष्य में नई संभावनाएं तलाश करने का नाम है। कभी-कभी सोचती हूं हमने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते क्यों नहीं देखा? क्या वो इंसानों से ज्यादा समझदार हैं? या उन्हें हम इंसानों से ज्यादा, भविष्य की चिंता, अगले दिन का बंदोबस्त, बच्चों की परवरिश इन सारे इंतेजामों पर ईश्वर पर अटूट विश्वास है। आने वाला साल सकारात्मक सोच के साथ जल, जीवन, जंगल, जीव और जलवायु के संरक्षण वाला हो यही कोशिशों के साथ आगे बढ़ने वाला हो।

हर व्यक्ति की स्वयं की, समाज की और राष्ट्र के प्रति कई जिम्मेदारियां होती हैं। ये छोटे-छोटे पल उन्हीं जिम्मेदारियों का आभास कराने का काम करते हैं। दुनिया भर में डर, दहशत, आतंक और दहशत की खबरें युद्ध जैसा माहौल बनाने का काम कर रही हैं। युद्ध का दौर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से दिखाई दे रहा है। हर बड़ी घटना के पीछे बहुत छोटी सी वजह मौजूद रहती है जो हरगिज युद्ध के लिए नहीं लेकिन युद्ध की वजह जरूर बनती है। इतिहास के हुए बड़े से बड़े युद्धों को देखें तो उसकी शुरूआत बहुत छोटी वजह से होती है। इसीलिए दुनिया को हमेशा से युद्ध की नहीं बुद्ध की आवश्यकता महसूस हुई और हम भारतीय तो गौरवांवित हैं कि हम बुद्ध की धरती पे रहते हैं। इतिहास गवाह है, दुनिया में शांति का परचम हमने लहराया है।

साल 2025 इसी शान्ति का हिमायती है। हम भारतीयों ने अमन का पैगाम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया है। अपने इस साल के संकल्पों में एक संकल्प अमन का भी याद रखना होगा। यहीं हमारी तरक्की की पहचान रही है। अपनी पहचान को कायम रखना हमारी अहम् जिम्मेदारी है। तभी भविष्य की ऊँची उड़ान भरना संभव है। आइए नए साल का आगाज नई आशाओं के साथ करें । जय हिन्द! जय भारत!

राजनीतिक मजबूरी का नाम है 'उप मुख्यमंत्री'

राज कुमार सिंह

समर्थकों के बीच 'दादा' के संबोधन से लोकप्रिय अजित पवार का मुख्यमंत्री बनने का सपना तो पता नहीं कब साकार होगा, लेकिन सबसे ज्यादा 6 बार उप मुख्यमंत्री बनने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड साल 2024 में उनके नाम हो गया। आश्चर्यजनक यह कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने भी शपथ 'उप मुख्यमंत्री' के रूप में ली, जबकि 'उप मुख्यमंत्री' या 'उप प्रधानमंत्री' पद का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। 1989 में जब चौधरी देवीलाल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रिमंडल में शपथ लेते हुए अपने लिए 'उप प्रधानमंत्री' पदनाम पढ़ा तो तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें टोक दिया था। दरअसल उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद संविधान में न होने के चलते उनकी हैसियत एक कैबिनेट मंत्री की ही होती है। इसलिए उन्हें उसी रूप में शपथ भी लेनी चाहिए, पर दुनिया भर में आदर्श शासन प्रणाली माने जाने वाले लोकतंत्र को भी हमारी राजनीति ने सत्ता का खिलौना बना दिया है। भारत के संविधान में उप मुख्यमंत्री पद न होने पर भी राज्य-दर-राज्य उप मुख्यमंत्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जाहिर है, यह संवैधानिक नहीं, बल्कि राजनीतिक मजबूरी है। देश के कुल 28 में से 16 राज्यों में इस समय कुल मिला कर 26 उप मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय, नागालैंड और ओडिशा में 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु और अरुणाचल में एक-एक उप मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु में तो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बेटे उदयनिधि को ही उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा करने वाले वह पहले राजनेता नहीं। प्रकाश सिंह बादल ने भी पंजाब का मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे सुखबीर सिंह बादल को उप मुख्यमंत्री बना दिया था। ऐसा भी नहीं कि किसी प्रदेश के बड़े आकार के मद्देनजर जनता को बेहतर शासन देने के मकसद से उप मुख्यमंत्री का पद सत्ताधीशों ने गढ़ लिया है, क्योंकि 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में एक भी उप मुख्यमंत्री नहीं, जबकि 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। आधे-अधूरे राज्य दिल्ली में भी मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री होते थे, जिन्हें शराब घोटाले में गिरफ्तारी के चलते इस्तीफा देना पड़ा। आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रैड्डी ने तो 5 उप मुख्यमंत्री बना दिए थे। जनादेश नहीं मिला, वरना हरियाणा में कांग्रेस की भी मंशा 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की थी।दरअसल आजादी के समय ही बिहार में अनुग्रह नारायण सिंह, देश में बनने वाले पहले उप मुख्यमंत्री थे। कभी राजनीतिक वरिष्ठता और गठबंधन राजनीति के दबावों से बनी जो 'व्यवस्था' अपवाद स्वरूप नजर आती थी, वह अब सत्ता के बंदरबांट का फॉर्मूला बन गई है। एक ही दल को स्पष्ट बहुमत मिलने पर भी उप मुख्यमंत्री बना कर क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधते हुए चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। मुख्यमंत्री एक वर्ग का बना कर अन्य प्रमुख वर्गों से उप मुख्यमंत्री बना देने को चुनावी जीत का नया फॉर्मूला मान लिया गया है। मसलन, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री राजपूत हैं तो ब्राह्मण और ओ.बी.सी. उपमुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। क्या इससे हमारे राजनीतिक दल इस खतरनाक सोच को ही बढ़ावा दे रहे हैं कि जाति - समुदाय विशेष का व्यक्ति ही अपने समुदाय के हित में काम कर सकता है और उसके वोट दिलवा सकता है। अगर नौकरशाही को भी लोग इसी नजर से देखने लगें, तब क्या होगा? ऐसी सोच संविधान के तहत ली जाने वाली उस शपथ का भी उल्लंघन है, जिसमें बिना राग-द्वेष सभी के प्रति समान भाव रखते हुए दायित्व निर्वाह की बात कही जाती है। अगर कहीं उस भावना का क्षरण दिख रहा है तो उसे ठीक करने की जरूरत है, न कि उसे बढ़ावा देने की। फिर यह सब चल कैसे रहा है? जाहिर है, सभी राजनीतिक दल सत्ता के ही खिलाड़ी हैं। इसीलिए वैचारिक मतभेदों के बावजूद उनमें सत्ता के ऐसे खेल पर मौन सहमति है। देश में इस समय जो 26 उप मुख्यमंत्री हैं, उनमें से सबसे ज्यादा 15 राजग के हैं। इनमें अकेले भाजपा के 13 हैं, जबकि राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस के 3। सुप्रीमकोर्ट ने साफ कर दिया कि अतिरिक्त राजनीतिक महत्व देने के लिए भले ही किसी को उप मुख्यमंत्री कह दिया जाए, पर वास्तव में वह होता मंत्री ही है, और वह किसी अतिरिक्त अधिकार या सुविधा का पात्र नहीं है।

मोहन भागवत का बयान देश की एकता-अखंडता के लिए महत्वपूर्ण

योगेंद्र योगी

भारत विश्व में तेजी से उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। भारत को 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था के अलावा भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के तौर पर तेजी से उभर रहा है। खाड़ी के मुस्लिम देश भारत के महत्व और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से द्विपक्षीय रिश्तों को स्वीकार कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत की इस ताकत को स्वीकारते हुए कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सर्वोच्च कुवैती सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। यह किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया गया 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अरबी भाषा में प्रकाशित रामायण और महाभारत की कृति कुवैतियों को सौंपी। इसका अनुवाद और प्रकाशन भी कुवैती मुसलमान ने किया है।

भारत इस दृष्टि से विश्व को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक सॉफ्ट पावर से अवगत करा रहा है। ऐसे में देश में चल रहे मंदिर-मस्जिद के ऐतिहासिक विवाद क्या भारत की इस तरक्की की रफ्तार में ब्रेक लगाने का काम करेंगे। इससे देश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा। पूर्व में इसी तरह के सांप्रदायिक विवादों की भारत ने जान-माल के नुकसान और वैश्विक निवेश को लेकर संशय के कारण बड़ी कीमत चुकाई है। इसी आंशका के कारण राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने धार्मिक स्थलों पर गढ़े मुर्दे उखाडने को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की है। भागवत को अंदाजा है कि ऐसे विवाद से भारत की छवि को नुकसान होगा। इससे कहीं न कहीं प्रगति पर भी असर पड़ेगा। यही वजह है कि संघ की धार्मिक कट्टर छवि के बावजूद भागवत ने ऐसे मुद्दे उठाने वालों को तगड़ी लताड़ लगाई है। भागवत ने पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के दौरान कहा कि कहीं मंदिर-मस्जिद के रोज़ नए विवाद निकालकर कोई नेता बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं। भागवत के भाषण की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस वक्त देश में संभल, मथुरा, काशी जैसे कई जगहों की मस्जिदों के प्राचीन समय में मंदिर होने के दावे किए गए हैं। इनके सर्वे की मांग हो रही है और कुछ मामले अदालतों में लंबित हैं।

भागवत ने कहा कि हमारे यहां हमारी ही बातें सही,

बाक़ी सब ग़लत, यह चलेगा नहीं। अलग-अलग मुद्दे रहे तब भी हम सब मिलजुल कर रहेंगे। हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ न हो इस बात का ख्याल रखेंगे। जितनी श्रद्धा मेरी मेरी खुद की बातों में है, उतनी श्रद्धा मेरी दूसरों की बातों में भी रहनी चाहिए। भागवत ने ये भी कहा कि रामकृष्ण मिशन में आज भी 25 दिसंबर (बड़ा दिन) मनाते हैं, क्योंकि यह हम कर सकते हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं और हम दुनिया में सब के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। यह सौहार्द अगर दुनिया को चाहिए तो उन्हें अपने देश में यह मॉडल लाना होगा। आरएसएस प्रमुख ने किसी विशेष विवाद का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं और वे चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आए। उन्होंने कहा, लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चलता है। इस व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो सरकार चलाते हैं। आधिपत्य के दिन चले गए हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन इसी तरह की दृढ़ता से जाना जाता था। हालांकि उनके वंशज बहादुर शाह जफर ने 1857 में गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था।

गौरतलब है कि राजस्थान के अजमेर शरीफ़ दरगाह से जुड़ा विवाद और संभल में एक मस्जिद से जुड़े ऐसे विवादित मुद्दों ने जोर पकड़ लिया था। अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने अजमेर शरीफ़ दरगाह के नीचे मंदिर का दावा करने वाली याचिका को हाल ही में स्वीकार कर लिया था। कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के बारे में भी इसी तरह का दावा किया गया था और जिला अदालत ने मामले में सर्वे का आदेश दिया था सर्वे के दिन ही संभल में हिंसा भी भड़की थी, जिसमें पुलिस ने चार लोगों की मौत की पुष्टि की थी। आरएसएस प्रमुख भागवत का यह बयान सभी को पच नहीं रहा है। दरअसल इस बयान ने हिन्दुत्व के नेतृत्व का विवाद पैदा कर दिया है। तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं हैं। बल्कि हम उनके अनुशासक हैं। वहीं, उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ पीठ के शंकरचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मोहन भागवत पर राजनीतिक रूप से सुविधाजनक रुख अपनाने का आरोप लगाया। सरस्वती ने कहा, जब उन्हें सत्ता चाहिए थी, तब वे मंदिरों के बारे में बोलते रहे। अब जब उनके पास सत्ता है तो वे मंदिरों की तलाश ना करने की सलाह दे रहे हैं।

अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि मंदिर और मस्जिद का संघर्ष एक सांप्रदायिक मुद्दा है और जिस तरह से ये मुद्दे उठ रहे हैं, कुछ लोग नेता बनते जा रहे हैं। अगर नेता बनना ही इसका मक़सद है तो इस तरह का संघर्ष उचित नहीं है। लोग महज़ नेता बनने के लिए इस तरह के संघर्ष शुरू कर रहे हैं, तो यह सही नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक? यहां सब बराबर हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बाकी संघ परिवार भागवत के बयान पर ध्यान देगा। कांग्रेस के ही एक और सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को ये रचनात्मक सलाह उन लोगों को देनी चाहिए जो संविधान का अपमान कर रहे हैं ताकि देश में शांति और समृद्धि बनी रहे। आरएसएस प्रमुख का बयान ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया पर मंदिर-मस्जिद के जहरीले बयानों की बाढ़ आई हुई है। भागवत ने वक्त की नजाकत को समझते हुए सही बयान दिया है। इससे देश की गंगा-जमुनी संस्कृति कायम रहेगी। ऐसे विवादित मुद्दों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने के लिए सांप्रदायिक एकता में दरार डालने कतिपय तत्वों के हौसले पस्त होंगे।

राजनीति के असली-नकली चमत्कारों का साल?

अमिताभ

वर्ष 2024 बीतने में तीन दिन बाकी हैं। किंतु गुजरते साल ने महाराष्ट्र की राजनीति में इतना उतार-चढ़ाव दिखाया कि उस पर कोई समझ विकसित कर पाना आज भी मुश्किल है। किसी भी राज्य के चुनावी साल में बिसात तो कुछ माह पूर्व से बिछने लगती है, लेकिन प्रदेश में पूरे पांच साल चुनाव के इंतजार में गुजरे और जब मतदाता के हाथ में निर्णय की घड़ी आई तो उसने सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिखाया। लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी दलों का अति आत्मविश्वास और विधानसभा चुनाव में विपक्ष की उम्मीद से अधिक अपेक्षा औंधे मुंह गिरे।

हालांकि परिणाम के बाद 'जो जीता वही सिकंदर' कहलाया, फिर भी परिणामों पर उठते सवाल राजनीति से समाज तक शोर करते रहे। चुनाव आयोग की निष्पक्षता से लेकर दलगत गड़बड़ियों पर आवाजें उठती रहीं। किंतु समाधान से अधिक परिणाम और कारण समझने में अधिक समय नहीं लगाया गया। संशय के आधार पर जीत-हार का जश्न-गम मनाया गया।

महाराष्ट्र में वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद नया साल कुछ नए परिदृश्य को लेकर ही आरंभ हुआ। पहले चुनाव के बाद दो सरकारों का विचित्र तरीके से गठन हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ था। फिर कुछ माह में महामारी कोरोना आ धमकी। दो साल के कोरोना संक्रमण की समाप्ति के बाद जब राज्य की महाविकास आघाड़ी

सरकार के पास कुछ करने का अवसर आया तो वह शिवसेना की बगावत का शिकार हो गई। फिर नई महागठबंधन की सरकार बनी और कुछ माह चलते ही उसके साथ राकांपा टूटकर जुड़ गई।

वर्ष 2022, 2023 टूटने और जुड़ने के रहे और उन्हीं के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारी आरंभ हुई। चूंकि लगभग दो सौ विधायकों के समर्थन से सरकार चल रही थी, इसलिए लोकसभा चुनाव में अपेक्षा गलत नहीं थी। किंतु 45 की अपेक्षा में महज 17 सांसद जीतने से सत्ताधारी गठबंधन को बड़ी निराशा हाथ लगी।

उसके बाद हावी विपक्ष के आगे विधानसभा चुनाव कड़ी चुनौती थे, लेकिन सत्ताधारी गठबंधन ने 230 सीटें जीतकर ऐसा चमत्कार किया कि विपक्ष उसे अभी तक समझ नहीं पाया है। दरअसल बीते पांच सालों में राजनीति में कई चमत्कार हुए और बीते साल में बारी मतदाताओं की थी, जिन्होंने आखिर अपना खेल दिखा दिया।

हालांकि चुनाव के बाद विजयी दल परिणामों की अपने ढंग से समीक्षा कर उपलब्धि बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि उन्हें यह मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि साल के दो चुनावों में मतदाता के मन की बात को पढ़ने में कोई भी दल सफल नहीं हो पाया। सब जानते हैं कि राज्य ही नहीं पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा के मामलों पर चर्चा कम नहीं होती है।

इसमें संविधान और आरक्षण आग में घी का काम करते हैं। किंतु राजनीतिक दल इन्हें अपनी सुविधा के साथ जनता के बीच ले जाते हैं और चुनाव परिणामों के बाद अपने ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं। दरअसल मुख्यालयों में बनने वाली चुनावी योजनाओं और धरातल की चिंताओं का कोई तालमेल नहीं बन पाता है। लोकसभा चुनाव के समय भी केंद्र की ओर से अनेक योजनाओं का प्रचार किया गया था।

सरकार को संविधान सहित जनता के सभी मामलों पर बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। मगर असलियत यही थी कि यह मतदाता का चमत्कार था, जो पक्ष-विपक्ष दोनों की समझ से बाहर था। वे मूल में छिपी बात समझ नहीं पाए। अब जब विधानसभा चुनाव की स्थिति बनी तो दूसरा चमत्कार हुआ। जहां एक ओर विपक्ष अपनी सत्ता में वापसी की तैयारी कर चुका था। वहीं विपक्ष के नेता पद के लिए संघर्ष करता दिखाई दिया। दूसरी ओर इतनी बड़ी सफलता के बाद सत्ता पक्ष के पास भी अपनी जीत की व्याख्या का बहुत बड़ा आधार नहीं था। इतना जरूर था कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष ने अपनी हार नहीं मानी, उसी तरह विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने अपनी पराजय को स्वीकार नहीं किया। दोनों असली-नकली जीत-हार में आम जनता को उलझाते रहे। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर शक से लेकर वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल(वीवीपैट) की पर्चियों की गिनती की मांग और समाधान जारी है, जिसमें आरोपों की पुष्टि नहीं हो पा रही है। परिणामों के कुछ माह बाद नेता यह भी मानने लगे हैं, कि वे अनेक बार ईवीएम से ही चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन मशीन से अधिक चिंता और अंदरूनी समस्या यह है कि मतदाता-नेता के बीच का फासला कुछ इतना अधिक हो चला है कि दोनों एक-दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। सामने दिखती पराजय पर भी दावे किए जा रहे हैं। सरकार, चुनाव, राजनीतिक दल अपनी परिपाटी पर चल कर दावों और नतीजों के बीच सामंजस्य बनाने में जुटे रहते हैं, लेकिन मतदाता के दिल की बात को समझ पाना मुश्किल ही होता है। चुनाव के नारे, सभाओं की भीड़, रोड शो का उत्साह, अलग-अलग मीडिया पर तरह-तरह का प्रचार चुनाव को किस मोड़ पर ले जा रहा है, यह समझना आसान नहीं रह गया है। यही कारण है कि जब परिणाम सामने आते हैं तो राजनीतिक दल कभी गम में बौखला जाते हैं तो कभी खुशियों में आपा खोने लगते हैं। यहीं से चुनाव के परिणामों के असली-नकली चमत्कार की परिभाषा गढ़ने के प्रयास आरंभ होते हैं, जो लोकतांत्रिक दृष्टि से अच्छे नहीं माने जा सकते हैं। इसे 'मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा' की तरह अंतिम फैसला ही मानना चाहिए। शायद बीते साल का यही संदेश भी है।

नए वर्ष की सुनहरी तस्वीर के साथ चुनौतियों की रेखाएं

आलोक मेहता

लंदन से आए एक मित्र ने पिछले दिनों मुझसे जानना चाहा कि नए वर्ष 2025 में भारत की राजनीतिक, आर्थिक स्थिति और शक्ति कैसी होगी ? मेरा उत्तर था कि भारत की वर्तमान प्रगति को देखते हुए यह कह सकता हूं कि 2025 में भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति न केवल बढ़ेगी, बल्कि दुनिया के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकती है। आशावादी होने के कारण हम जैसे पत्रकार यह कह सकते हैं कि सारी कमियों, गड़बड़ियों, हिंसा, आंदोलन और भ्रष्टाचार आदि के बावजूद भारत कमजोर नहीं होने वाला है। वर्ष की शुरुआत ही प्रयाग के महाकुम्भ पर्व से होने वाली है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक आस्था के साथ करोड़ों लोगों को जोड़ने वाला है। इसी तरह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर रुसी राष्ट्रपति या अन्य राष्ट्राध्यक्ष के परेड समारोह में भारत की बढ़ती आधुनिक सैन्य शक्ति और भारत में तेजी से हो रही आर्थिक प्रगति, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता के साथ एकता के दर्शन दुनिया को होंगे। पिछले दस वर्षों और खासकर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, संसद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसलों का लाभ 2025 में दिखने लगेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रादेशिक स्वायत्तता और प्रतियोगिता के कारण बेटियों को पढ़ाने-बढ़ाने और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य की लाभकारी योजनाओं का लाभ मिलता दिखाई देगा। लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि सम्पन्न विकसित देश अमेरिका के सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति भी ओबामा केयर स्वास्थ्य योजना लागू नहीं कर सके हैं। इसी तरह ब्रिटेन में तो सामान्य जनता की नेशनल हेल्थ सर्विस बुरी तरह चरमराई हुई है। भारत में सरकारी या प्राइवेट अस्पताल अथवा छोटे क्लीनिक के अलावा आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र उपलब्ध हैं। अब तो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के परिवार को प्राकृतिक चिकित्सा के लिए भारत आना पड़ रहा है। नए वर्ष का प्रारम्भ दिल्ली विधानसभा चुनाव से होगा और साल की अंतिम तिमाही में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक केंद्र शासित दिल्ली और दूसरे विशाल बिहार के चुनाव कई मायनों में भारत के राजनैतिक दलों की दशा-दिशा और भविष्य तय करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने और संसद, विधानसभाओं में महिला आरक्षण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए, उसी तरह समान नागरिक संहिता और एक देश एक चुनाव के अपने लक्ष्य को अधिकाधिक समर्थन जुटाकर संसद से स्वीकृति लेकर नया इतिहास बनाने की चुनौती रहने वाली है। इन निर्णयों के दूरगामी परिणाम होंगे। विश्व में अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारत के समान स्तर पर घनिष्ठ संबंधों का असर नए वर्ष में दिखेगा।

उपहार का ऐसा लेनदेन ना ही करो तो बेहतर

बेबी की दोस्त अलका ने कान में जो टॉप्स पहने थे उसमें एक सफेद मोती चिपका था। वो बड़े जतन से उसे संभाल कर पहने थी। कहीं गिर न जाएं। बेबी ने पूछा ऐसे क्यों कर रही ? अलका ने बड़े प्यार और गर्व से बताया कि मेरी भाभी नेपाल से ये टॉप्स सच्चे मोती के लाई है। बहुत महंगे हैं। सुन कर बेबी जोर-जोर से हंसने लगी। बोली ये टॉप्स आड़ा बाजार के हैं। ठेलों में दस-दस रूपये में मिल रहे हैं। तेरी भाभी जब खरीद रही थी तब मैं भी वहीं खड़ी थी। ये देख मैंने भी लिये। अलका का मुंह उतर गया। शर्मिंदगी होने लगी खुद पर। सोचने लगी उसकी भाभी ने ऐसा उसके साथ क्यों किया? पर कोई कारण उसे समझ ही नहीं आया। एक बार लक्ष्मी को डॉक्टर ने हवा पानी बदलने की सलाह दी। ज्यादा दूर जाने की बजाय उसके घर के लोगों ने उन्हें पचमढ़ी जाने की सलाह दी। उस की बड़ी बहन भी भोपाल ही रहती थी तो उसे भी ठीक लगा। वहां एक रात रुकने का इरादा किया। अगली सुबह पचमढ़ी, फिर वापिस इंदौर लौट आने का कार्यक्रम तय हो गया। अपनी नन्ही सी बेटी के साथ निजी वाहन में चल पड़े। शादी के बाद पहली बार बहन के घर जा रहे थे। बड़े खुश थे। रात को पहुंच कर खाना खाया और सुबह निकलने की तैयारी की। बहन हाथ में कुछ पैकेट लिए आई। कंकू लगाया और पैकेट थमा दिए। लक्ष्मी ने ऐसे के ऐसे ही बेग में रख लिए। तय कार्यक्रम से पचमढ़ी टूर पूरा किया, घर लौट आये। सभी के सामने बड़ी बहन के दिए गिफ्ट खोले। उसमें लक्ष्मी की सालभर की गुडिया का छोटा सा गर्मियों में पहनने सा दो बद्दी वाला लेडिस रुमाल के जितने कपड़े वाला फ्राक/झबला, पति के लिए खादी का कुरता, लक्ष्मी के लिए सलवार कुर्ता था।

यहां तक तो ठीक है पर जब देखा तो उसमें प्राइज टेग लगे थे। उनमें सभी की कीमत लिखीं थी। जानते हैं उनमें क्या कलाकारी थी? उसने उन सभी में अंक बढा दिए थे। किसी में आगे जीरो किसी में पीछे संख्या। साथ ही जिस पेन से किये उनकी स्याही का रंग व लिखावट में भारी अंतर था। वो भूल गई की सभी अन्न खाते हैं। लक्ष्मी के ससुर उसी वक्त घर के सामने ही खादी ग्रामोद्योग की दुकान गए और वहां से उनकी असल कीमत जानी। कितनी हद है यह तो। आपने अपनी मर्जी से दिए थे न, तो फिर ऐसी नालायकी करने की क्या जरुरत आ पड़ी। उसकी बहन का पति बैंक मनेजर, वो खुद सेंट्रल गवरमेंट की अच्छी खासी नौकरी में थी। शायद लक्ष्मी व उसके पति को उसने अपनी झूठी शान की छाप छोड़ने के लिए ऐसी बेवकूफाना हरकत की हो। पर ये निरी परम मूर्खता ही थी। जिससे लक्ष्मी को तो लज्जित होना ही पड़ा, संबंधों में भी आजन्म खटास पैदा हो गई। लक्ष्मी ने तुरंत यह कह कर सब वापिस भेज दिए कि हम इतने महंगे कपड़े नहीं पहनते। उसकी बहन को समझ तो सब आ गया था पर जिसकी आंखों और अक्ल में बेशर्मी की पट्टी चढ़ी होती है उसे कुछ भी दिखाई जो नहीं देता। और ऐसे लोग ऐसी हरकतों से बाज भी नहीं आते। कभी 'म्यांमार' की साड़ी पहनी है आपने? साडियां पहनने वाला भारत देश अब म्यांमार से साड़ी बुलवाएगा। सोच कर ही तरस आता है ऐसे लोगों पर। निधि के मकान का वास्तु हुआ था। उसकी मामी ने एक साड़ी उसे यह कहकर ओढाई की तेरे मामा इसे म्यांमार से तेरे लिए लाये हैं। हरे रंग की मोटे रेग्जिन से कपड़े वाली साड़ी का वे जोर जोर से सबके बीच 'इम्पोर्टेड है' कह कर बखान रहे थे। निधि पढी-लिखी डॉक्टरेट थी। पर चुप थी।

उसकी भाभी ने बताया की यह साड़ी मामी को उनके पीहर से उनकी भाभी ने दी थी जो इन्हें पसंद नहीं आई। आनी भी नहीं थी। हम भारतवासीयों को 'म्यांमार' की साड़ी कैसे पसंद ? बस उन्होंने 'टिका' दी निधि को। अकेले में निधि ने मामी से पूछ ही लिया कि 'मामी विदेशों में वो भी म्यांमार जैसी जगह साडियां कैसे? मैंने तो कहीं पढ़ा-सुना नहीं। यदि हैं तो गईं भारत से ही होंगी न? वैसे ऐसी साड़ी मैंने आपके पीहर में किसी के पास देखी है।'

बस मामी को काटो तो खून नहीं। उनका दांव फेल जो हो गया था। आज की भाषा में 'एक्सपोज' होना कहते हैं इसे। क्यों करते हैं लोग ऐसा समझ से ही परे है। इन सभी परिस्थितियों को आपको खुद ही अपनी बुद्धि व विवेक से परिस्थितियों के मद्देनजर निपटना व सुलझाना होता है। इस बीमारी का कोई परमानेंट ईलाज आज तक नहीं मिल पाया है। 'जैसे को तैसा' वाला फार्मूला चला सकें तो लगाइए। वरना भुगतें। सहन करें। या 'मुंह फट' हो जाइए। क्योंकि ऐसा ही कुछ आपके, हमारे, हम सभी के साथ कभी न कभी घटता है। यदि नहीं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं।

ये सारे लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते। यहीं होते हैं हमारे साथ, हमारे आस-पास। कुछ अपने कुछ पराये जिन्हें दूसरों के साथ ऐसा करने की गन्दी लत पड़ी होती है। यह तो कुछ छोटे से, जरा से ही उदाहरण मैंने पेश किए हैं। इनके आलावा भी कई और कई प्रकार के , कई मौकों पर गिफ्ट-गेम इज्जत का फलूदा करते-कराते खेले जाते हैं और खेले जाते रहेंगे। कारण कई हो सकते है क्योंकि ये जीवन है, इस जीवन का यही है.

सर्दियों के मौसम में कपड़ों से नहीं आएगी दुर्गन्ध

अपनाएं ये आसान टिप्स

सर्दियों के मौसम में हवा में नमी होने की वजह तो कई बार गलत तरीके से कपड़ों की सफाई करने से तो कभी गलत तरीके से कपड़े को रखने से बदबू आने लगती है। अगर कपड़े की सफाई से लेकर उसे रख-रखाव पर अच्छे से ध्यान दिया जाए तो किसी भी मौसम में कपड़ों से बदबू नहीं आएगी।

यार, 'आज ही तो इसे अलमारी से निकाला है पहनने के लिए और पता नहीं इस ड्रेस से अजीब किस्म की दुर्गंध आ रही है'। कुछ दिन पहले भी स्वेटर और कोट निकाला था पहनने के लिए उससे भी ठीक ऐसी ही दुर्गन्ध आ रही थी'। शायद, आपने ने भी किसी न किसी से ये शब्द जरूर सुना होगा कि गर्मी के मौसम तो नहीं लेकिन, सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों से लेकर अन्य कपड़ों से एक अजीब किस्म की बदबू आती है। ऐसे में अगर अन्य कपड़ों से लेकर सर्दियों के कपड़ों से कुछ अजीब किस्म की बदबू आती है, तो फिर आपको इस लेख को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि, इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप किसी भी कपड़े से दुर्गन्ध को आसानी से दूर कर सकती हैं, तो आइए जानते हैं।

गुलाब जल का इस्तेमाल करें

जी हां, सर्दियों में कपड़ों से किसी भी दुर्गन्ध को दूर करने के लिए जुलाब जल एक बेस्ट उपाय हो सकता है। इसके इस्तेमाल से ऊनी पकड़ों से लेकर अन्य कपड़ों से भी दुर्गन्ध आसानी से गायब हो सकती है। इसके लिए फ्रेश कपड़ों पर छिड़काव करने की जरूरत नहीं बल्कि, सफाई के दौरान इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके लिए फॉलो करें आसान स्टेप्स-

- सबसे पहले दो से तीन लीटर पानी में तीन से चार चम्मच नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर को डालकर एक मिश्रण तैयार कर लीजिए।
- अब आप इस घोल में कपड़े को डालकर कुछ देर बाद अच्छे से साफ कर लें।
- इसके बाद तीन से चार लीटर पानी में साफ किए कपड़े को अच्छे से धो लें।
- फिर से एक से दो लीटर पानी में एक से दो चम्मच गुलाब जल को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और इस पानी में साफ किए कपड़े को डालकर कुछ देर ले लिए छोड़ दें।
- लगभग 5 मिनट बाद पानी में से कपड़े को निकालकर अच्छे से पानी को निचोड़ लें और धूप में रख दें।
- ध्यान रहे जब तक कपड़ा एकदम ठीक से सुख न जाए तब तक उसे अलमारी में न रखें।
- इससे कपड़े में से कभी भी बदबू नहीं आएगी। कपड़ा हमेशा सुगन्धित रहेगा।

ऊनी कपड़ों से ऐसे करें दुर्गन्ध को दूर

सर्दी के मौसम अगर सबसे अधिक किसी कपड़े से अजीब किस्म की बदबू आती है, तो वो है ऊनी के कपड़े। कई बार गलत तरीके से स्टोर करने या फिर नमी वाली जगह रखने पर इससे दुर्गन्ध आने लगती है। कई बार ठीक से सफाई न करने या फिर गलत डिटर्जेंट के इस्तेमाल करने से भी बदबू आने लगती है। ऐसे में ऊनी कपड़ों से किसी भी बदबू को दूर करने के लिए आप लैवेंडर ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए फॉलो करें ये आसान स्टेप्स-

- सबसे पहले तीन से चार लीटर पानी में इजी लिक्विड डालकर अच्छे से मिक्स कर लें।
- अब इस घोल में स्वेटर और अन्य ऊनी के कपड़ों को डालकर लगभग 10 मिनट के बाद अच्छे से साफ कर लें।
- अब इन कपड़ों को फ्रेश पानी में अच्छे से साफ कर लें।
- इसके बाद दो से तीन लीटर पानी में एक चम्मच लैवेंडर ऑयल अच्छे से मिक्स कर लें और इस मिश्रण में साफ ऊनी के कपड़े डालकर निकाल लें और अच्छे को पानी निचोड़ लें। इसके बाद इसे धूप में अच्छे से सुखने के लिए रख दें। इससे ऊनी कपड़ों से कभी भी दुर्गन्ध नहीं आएगी।

इन टिप्स को भी आप कर सकती हैं फॉलो

सर्दियों के मौसम में कपड़ों से दुर्गन्ध को दूर करने के लिए आप सिर्फ जुलाब जल या लैवेंडर ऑयल का ही इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं बल्कि, इसके अलावा कई चीजें हैं जिसके इस्तेमाल से आप कपड़ों से दुर्गन्ध को दूर कर सकती हैं। सफाई के दौरान आप एक से दो चम्मच सिरका, चन्दन के तेल के अलावा आप अन्य किसी सेंटेड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

इन बातों का भी रखें विशेष ध्यान

- सर्दियों के मौसम में किसी भी कपड़े को नमी वाली जगह रखने से बचें।
- ऊनी कपड़े या अन्य कपड़ों को कुछ समय के लिए धूप में जरूर रखें।
- वाशिंग मशीन में कपड़ों को साफ करते समय आप उसमें गुलाब जल, जैस्मिन ऑयल या फिर अन्य सेंटेड ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं।
- अलमारी या अन्य जगह रखें कपड़ों पर आप सुगंधित स्प्रे का छिड़काव कर सकती हैं या सुगंधित स्प्रे से कॉटन को अच्छे से भिगोकर अलमारी में भी रख सकती हैं।
- अगर कपड़े में हल्का भी नमी है तो उसे फोल्ड करके अलमारी में न रखें बल्कि उसे हवा के नीचे रखें।
- सर्दियों के मौसम में ऊनी और अन्य कपड़ों को अलग-अलग रखने की कोशिश करें।

ड्राइंग रूम की सजावट में रखें इन बातों का ध्यान

वास्तु शास्त्र में कोई भी भवन खरीदते या उसकी सजावट करते समय कई बातों का ध्यान देना आवश्यक बताया गया है, क्योंकि घर का मुख्य कक्ष, बैठक कहें या ड्राइंग रूम वह जगह है, जहां हम अपने परिवारजनों और कुछ खास मित्रों के साथ कुछ क्षण आनंद से गुजारना चाहते हैं। अक्सर देखने में आता है कि किसी अन्य मित्र के घर के ड्राइंग रूम में जाने पर हमें अजीब-सा भारीपन महसूस होता है, जबकि दूसरे मित्र के ड्राइंग रूम में हल्कापन लगता है। आइए जानें कैसी हो ड्राइंग रूम की सजावट

- ड्राइंग रूम में प्रकाश, घड़ी, कैलेंडर और तस्वीरों के चयन में भी सावधानी रखी जानी चाहिए।
- विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि वे तनाव बढ़ाने वाले न हों। जहां तक हो सके प्रयास किया जाए कि अध्ययन कक्ष, बेडरूम तथा अन्य कक्षों के भीतरी भाग बैठक से नजर न आएं।
- बैठक से अध्ययन कक्ष की मेज तथा काम के अन्य उपकरण दिखाई देने से भी बैठक में तनाव बढ़ता है।
- वास्तु और फेंगशुई के प्रचार के बाद से वास्तव में लोग अपने मकान के निर्माण या बना-बनाया फ्लेट खरीदते समय वास्तु आदि पर ध्यान तो देने लगे हैं, किंतु मकान में प्रवेश करने के बाद उसकी सजावट करते हुए वास्तु और फेंगशुई को प्राय: भूल जाते हैं।
- जबकि सोफा, टेबल आदि फर्नीचर का आकार, दीवारों की सजावट, चित्रों की विषय वस्तु, प्रकाश व्यवस्था आदि सब मिलकर वास्तु का प्रभाव तय करते हैं।
- दरवाजे के ठीक ऊपर लगा कैलेंडर या बंद पड़ी घड़ी से भी बैठक की अच्छी ऊर्जा प्रभावित हो जाती है।
- फर्नीचर खरीदी करने का तरीका अक्सर यह रहता है कि दुकान पर गए, जो पसंद आया, उठा लाए। फिर चाहे वह बैठक के अनुपात में हो, रंगों आदि से मेल खाता हो या न हो।
- ड्राइंग रूम के आकार के अनुपात से बड़ा सोफा अच्छी ऊर्जा अर्थात ची को प्रभावित करता है और भारी सोफा गृहस्वामी के अलावा आगंतुकों के लिए भी भारीपन की रचना करता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि ड्राइंग रूम के लिए फर्नीचर का चुनाव करते हुए उनके आकार का ध्यान जरूर रखें।

अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या वह पढ़ाई से जी चुरा रहा है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता हैं तो आप नीचे दिए गए टिप्स के अनुसार बच्चे के कमरे में वास्तु परिवर्तन करेंगे तो निश्चित ही वह मन लगाकर पढ़ेगा तथा उसका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा।

अगर ऐसा होगा आपके बच्चे का रूम तो पढ़ाई में होगा सर्वश्रेष्ठ

- बच्चों के कमरे में पर्याप्त रोशनी आनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी हो कि दिन में पढ़ते समय उन्हें कृत्रिम रोशनी की आवश्यकता ही न हो।
- जहां तक संभव हो सके, बच्चों के कमरे की उत्तर दिशा बिलकुल खाली रखना चाहिए।
- उनके किताबों की रैक नैऋत्य कोण में स्थित हो सकती है।
- खिड़की, एसी तथा कूलर उत्तर दिशा की ओर हो।
- बच्चों के कमरे में स्थित चित्र एवं पेंटिंग्स की स्थिति उनके विचारों को प्रभावित करती है इसलिए हिंसात्मक, फूहड़ एवं भड़काऊ पेंटिंग्स एवं चित्र बच्चों के कमरे में कभी नहीं होना चाहिए।
- महापुरुषों के चित्र, पालतू जानवरों के चित्र, प्राकृतिक सौंदर्य वाले चित्र तथा पेंटिंग्स बच्चों के कमरे में हो सकती हैं।
- भगवान गणेश तथा सरस्वती जी का चित्र कमरे के पूर्वी भाग की ओर होना चाहिए। इन दोनों की देवी-देवताओं को बुद्धिदाता माना जाता है अत: सौम्य मुद्रा में श्री गणेश तथा सरस्वती की पेंटिंग या चित्र बच्चों के कमरे में अवश्य लगाएं।
- आपका बच्चा जिस क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहा है, उस करियर में उच्च सफलता प्राप्त व्यक्तियों के चित्र अथवा पेंटिंग्स भी आप अपने बच्चों के कमरे में लगा सकते हैं।
- यदि बच्चा छोटा हो, तो कार्टून आदि की पेंटिंग्स लगाई जा सकती है।
- बच्चों के कमरे में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि घर में होने वाला शोरगुल उन्हें बिलकुल बाधित न करे अत:
- बच्चों के कमरे से घर की तरफ कोई खिड़की या झरोखा खुला हुआ नहीं होना चाहिए।
- बच्चों की श्रेष्ठ उन्नति के लिए उनके कमरे का वास्तु के अनुकूल होना आवश्यक है।
- यदि उपर्युक्त तथ्यों में आपके बच्चों के कमरे में कोई कमी है, तो उसे परिवर्तित कर वास्तु के अनुकूल बना सकते हैं। ऐसा करने पर निश्चित रूप से आपके बच्चे के मानसिक विकास एवं उसकी ग्राह्य क्षमता में परिवर्तन नजर आएगा।

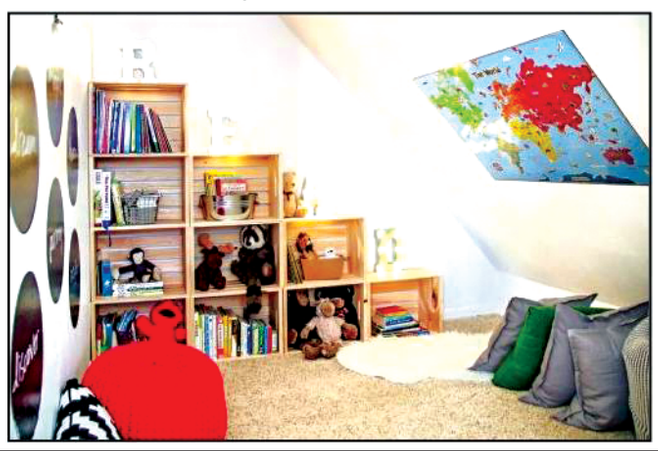

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राहुल गांधी ने बाउंसर जैसा किया व्यवहार : प्रताप सारंगी

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उनके व्यवहार को लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद के लिए उपयुक्त होने के बजाय बाउंसर बताया है। यह पद कभी अटल बिहारी वाजपेयी जैसी प्रतिष्ठित हस्तियों के पास था। संसद में हाथापाई के बाद घायल हुए और अस्पताल में भर्ती कराए गए सारंगी ने कहा कि वह अब तुलनात्मक रूप से बेहतर हैं और उन्हें 28 दिसंबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 19 दिसंबर की संसद हाथापाई की घटना को याद करते हुए, सारंगी ने कहा, यह तब हुआ जब हम (भाजपा सांसद) एक प्रवेश द्वार के पास खड़े थे, शांतिपूर्वक तख्तियां लिए हुए अंबेडकर के अपमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अचानक राहुल गांधी अपनी पार्टी के कुछ साथियों के साथ आए और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगे। वह लोकसभा में विपक्ष के नेता की तरह नहीं, बल्कि एक बाउंसर की तरह व्यवहार कर रहे थे।

आतिशी-संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे संदीप

नईदिल्ली। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच बढ़ते विवाद के बीच नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने मंगलवार को कहा कि वह दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक और नागरिक मानहानि का मामला दायर करेंगे। यह कदम मतदान से ठीक पहले आतिशी द्वारा दीक्षित पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से धन लेने का आरोप लगाने के आरोपों के जवाब में उठाया गया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि 5-6 दिन पहले दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा था कि मैं बीजेपी से बड़ी रकम ले रही हूं। पिछले 10-12 सालों से उन्होंने कांग्रेस, मुझे और मेरे परिवार को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास पिछले 10-12 वर्षों से आप से पूछने के लिए कई प्रश्न हैं...वह (अरविंद केजरीवाल) शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ 360 पत्रों के सबूत लेकर घूमते थे।

बांसुरी स्वराज का आतिशी सरकार पर वार

नईदिल्ली। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात के अगले दिन भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे शर्मनाक बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सात महीने से भुगतान नहीं किया गया है और आशा कार्यकर्ताओं का वजीफा नहीं बढ़ाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि दिल्ली की आप सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछले सात महीने से वेतन नहीं दिया है। आशा वर्कर 3000 रुपये वेतन पर काम कर रही हैं और उनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है। उन्होने कहा कि हर तीन साल में उनका वजीफा बढ़ाया जाना चाहिए। कानून इसे अनिवार्य बनाता है। यह आप सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। इस संबंध में दिल्ली के एलजी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वह इस मुद्दे पर दिल्ली के सीएम को निर्देश देंगे।

केजरीवाल ने शुरू की पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पुजारी-ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की। केजरीवाल ने मरघट वाले बाबा के दर्शन कर इस योजना को शुरू किया। मंगलवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ कश्मीरी गेट स्थित मरघट वाले बाबा मंदिर गए। यहां उन्होंने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान केजरीवाल ने खुद पुजारी का रजिस्ट्रेशन किया। पहले हनुमान मंदिर से योजना शुरू करने का प्लान था। इस दौरान केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने रजिस्ट्रेशन रोकने की कोशिश की। लेकिन भक्त को भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इस योजना के अनुसार, दिल्ली में आप की सरकार पुजारी और ग्रंथियों को 18 हजार रुपये की सैलरी देगी। सोमवार को ही अरविंद केजरीवाल ने इस योजना का एलान किया था। यहां के महंत का मंगलवार को जन्मदिन है। केजरीवाल ने उनके साथ जन्मदिन भी मनाया।

बिहार में झामुमो ने चुनाव लड़ने 12 सीटों पर ठोंका दावा

रांची। झारखंड के बाद साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इसे लेकर राजनीतिक पारा फिर से चढ़ा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह राज्य की सबसे पार्टी झामुमो भी इस बार गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी कम से कम 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो झामुमो बिहार में राजद और कांग्रेस से 12 सीटों की मांग करेगा। इसके पीछे पार्टी का तर्क है कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में पार्टी का मजबूत जनाधार है। पूर्व में पार्टी के विधायक भी वहां से रहे हैंख। जानकारी के मुताबिक झामुमो बिहार की जिन सीटों पर दावा कर रहा है उनमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रूपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपख्ती और चकाई विधानसभा की सीट शामिल है। बताया गया कि जल्द ही राजद और कांग्रेस गठबंधन के साथ झामुमो की बैठक होगी और इस मांग को रखा जायेगा।

वैश्विक भू-राजनीति के लिए अहम रहेगा साल 2025

- ट्रंप 2.0 से लेकर महाकुंभ मेला और विधानसभा चुनाव तक

नई दिल्ली। साल 2024 का आज आखिरी दिन हैं। ये साल कई मायनों में चौंकाने वाला साल रहा और भारत के पड़ोस में भी कई नाटकीय घटनाक्रम हुए। बहरहाल अब लोग 2025 के स्वागत के लिए तैयार है। साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि अगले साल राजनीतिक और वैश्विक स्तर पर कौन सी ऐसी बातें हैं, जिन पर सभी का ध्यान रहेगा। तो आइए जानते हैं कि किन-किन बातों पर 2025 में दुनिया की नजरें रहेंगी।

डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल

डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप ने डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर चुनाव जीता था और 20 जनवरी को वे राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप के पुराने रिकॉर्ड और उनके हालिया बयानों को देखते हुए ट्रंप के कार्यकाल पर सभी की नजरें रहेंगी। ट्रंप की कैबिनेट में भी कई ऐसे नाम हैं, जिन पर लोगों की नजरें रहेंगी, उनमें दिग्गज उद्योगपति एलन मस्क का नाम भी शामिल हैं, जिन्हें ट्रंप ने सरकार के खर्चे कम करने की जिम्मेदारी दी है। ट्रंप ने हाल ही में कनाडा पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने, पनामा नहर पर कब्जा करने और ग्रीनलैंड को लेकर बयानबाजी की है। साफ है कि ट्रंप की कई योजनाएं हैं, जिनसे राजनीतिक तौर पर उथल-पुथल हो सकती है। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स और अवैध अप्रवासन को लेकर भी बयानबाजी की है। ऐसे में ट्रंप के कार्यकाल के शुरुआती दिनों पर सभी की निगाहें रहेंगी।

इस साल बांग्लादेश और सीरिया में

तख्तापलट ने पूरी दुनिया को चौंकाया। साथ ही श्रीलंका में अनुरा कुमारा दिसानायके को प्रचंड जीत मिली। पाकिस्तान में भी पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी द्वारा लगातार बगावत का बिगुल फूंका जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान में भी राजनीतिक संकट लगातार गहरा रहा है। यूरोप, फ्रांस और जर्मनी में सरकारें अल्पमत में चल रही हैं और वहां भी राजनीतिक संकट बढ़ रहा है। वहीं पश्चिम एशिया का संकट अभी भी बना हुआ है और रूस-यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है और इसके बढ़ने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में नए साल में वैश्विक भू-राजनीति पर भी नजरें बनी हुई हैं और नए साल में भी कुछ चौंकाने वाले घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं।

महाकुंभ मेला

13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत हो रही है, जो फरवरी तक चलेगा। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, जहां करोड़ों लोग आते हैं। महाकुंभ मेले में भी करीब 40 करोड़ लोगों को आने की उम्मीद है। कुंभ मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के तट पर लगता है। यूनेस्को ने कुंभ मेले को सांस्कृतिक विरासत के रूप में वर्गीकृत किया है। पिछली बार महाकुंभ मेला साल 2013 में आयोजित हुआ था, तब इसमें 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे। हिंदुओं का मानना है कि कुंभ मेले के दौरान संगम में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं।

इन राज्यों के चुनाव पर रहेंगी नजर

साल 2025 में राजधानी दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के साथ ही ये चुनाव भारतीय राजनीति के तीन ब्रांड्स के बीच का भी चुनाव माना जा रहा है, जिनमें पीएम मोदी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है। बीते करीब दो दशकों से बिहार के सीएम पद पर काबिज नीतीश कुमार के लिए आगामी विधानसभा चुनाव एक बड़ी परीक्षा है। नीतीश के साथ ही तेजस्वी यादव के लिए भी अपनी ताकत साबित करने के लिए आगामी चुनाव अहम होंगे। आबकारी नीति मामले में जेल जाने के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का काफी कुछ दांव पर है। ये चुनाव पीएम मोदी की ब्रांड वैल्यू के लिहाज से भी अहम होंगे क्योंकि बिहार और दिल्ली दोनों ही राज्य ऐसे हैं, जहां भाजपा अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

कई विधेयकों पर भी रहेंगी नजरें

सरकार ने बीते शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश कर दिया है। फिलहाल संसद की संयुक्त समिति इस पर चर्चा करेगी। अगले साल इस विधेयक के पारित होने की उम्मीद है। यह विधेयक पारित होता है तो इससे देश की राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। साथ ही ऐसी भी चर्चाएं हैं कि सरकार समान नागरिक संहिता जैसे फैसलों पर भी विचार कर सकती है। इनके अलावा जनगणना भी अगले साल शुरू होनी है। साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक भी जेपीसी के पास है, जिसे लेकर काफी चर्चाएं

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का वियतनाम दौरा एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। उन्होंने यह भी कहा कि करोड़ों लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर राहुल गांधी की आंखों में आंसू देखे थे।

सबसे पुरानी पार्टी के नेता ने कहा, राहुल गांधी पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम की वजह से वियतनाम गए थे। करोड़ों लोगों ने डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर उनकी आंखों में आंसू देखे थे।

इससे पहले आज भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर वियतनाम यात्रा को लेकर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि गांधी के लिए एलओपी का मतलब 'Leader of Partying' (बंटवारा करने वाला नेता) है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी ने अवकाश को प्राथमिकता दी जबकि देश शोक मना रहा था और यह उनके द्वारा डॉ. मनमोहन सिंह को फादर फिगर (पिता समान व्यक्ति) कहे जाने के बावजूद अपमानजनक था।

कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने अपनी पार्टी के नेता का बचाव करते हुए कहा कि यह सब भाजपा की ओर से ध्यान भटकाने की राजनीति है। उन्होंने कहा, संगठनों को ये डायवर्ट राजनीति कब बंद होगी? जिस तरह से मोदी जी ने डॉ. साहब को यमुनापार शमशान घाट में जलाने का स्थान नहीं दिया और उनके परिवार को घेरे में लिया, वह शर्मनाक है। अगर गांधी ने निजी यात्रा की है तो आपको क्यों परेशानी हो रही है?

इससे पहले सोमवार को भाजपा विधायक अलेटी महेश्वर रेड्डी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि वे इंग्लिश न्यू ईयर मनाने के लिए वियतनाम यात्रा पर गए, जबकि पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर

शोक मना रहा था।

डॉ. मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को दिल्ली में आयु संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण निधन हो गया था। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निगमबोध घाट पर राज्य सम्मान के साथ हुआ, जहां उनके परिवार, दोस्तों, सहयोगियों और सरकारी अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

भाजपा दलित-आदिवासियों के खिलाफ जातिगत अत्याचारों को दे रही बढ़ावा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग दलितों और आदिवासियों के खिलाफ जातिगत अत्याचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। खासकर उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश।

खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह बाबासाहेब आंबेडकर का अपमान करते हैं और वही जातिवादी मानसिकता भाजपा-शासित राज्यों में दोहराई जा रही है। उन्होंने भाजपा की सरकार को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि मोदी शासन के तहत दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं।

उन्होंने कहा, यह सच है कि मोदी सरकार के संविधान विरोधी शासन के तहत दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार हो रहे हैं। जो गरीब और वंचित हैं, वे मनुवाद का शिकार हो रहे हैं। हर घंटे दलित-आदिवासी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं और एनसीआरबी के अनुसार, 2014 के बाद इन घटनाओं में दो गुना वृद्धि हुई है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने हालिया जातिगत अत्याचारों के कुछ उदाहरणों का हवाला दिया, जिनमें मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस हिरासत में एक दलित युवक की मौत, ओडिशा के बालासोर में एक आदिवासी महिला को पेड़ से बांधकर पीटने की घटना, हरियाणा के भिवानी में एक दलित छात्रा द्वारा आत्महत्या करने की घटना, महाराष्ट्र के पालघर में एक आदिवासी महिला की मौत और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तीन दलित परिवारों को जातिगत हमलों के कारण पलायन करने के मामले शामिल हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस 140 करोड़ भारतीयों के संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देगी। कांग्रेस भाजपा-आरएसएस की संविधान विरोधी सोच के खिलाफ लगातार संघर्ष करती रहेगी।

खेल
प्रमुख समाचार

टेस्ट क्रिकेट के भविष्य पर रोहित लेने वाले हैं फैसला?

मेलबर्न। पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के बाद कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। रोहित के लगातार विफल रहने के बाद कुछ पूर्व क्रिकेटरों सहित प्रशंसकों ने उनके टेस्ट क्रिकेट के भविष्य पर सवाल खड़े किए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के शीर्ष अधिकारी और चयनकर्ता पहले ही इस फैसले के बारे में बात कर चुके हैं और इसकी बहुत कम संभावना है कि रोहित अपना मन बदलेंगे।

इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है रोहित इसका एलान कब करेंगे, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो वह सिडनी में तीन जनवरी से होने वाले पांचवें टेस्ट के बाद टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि, अगर भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहा तो रोहित चयनकर्ताओं से खिताबी मुकाबले में बने रहने की कोशिश कर सकते हैं। रोहित चौथे टेस्ट मैच में हार के बाद कहा था कि यह नतीजे मानसिक रूप से परेशान करने वाले हैं और उन्हें भी कुछ चीजों पर गौर करने की जरूरत है। रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं आज जहां खड़ा हूं वहीं खड़ा हूं। अतीत में क्या हुआ, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है, कुछ नतीजे हमारे अनुकूल नहीं रहे। हां, एक कप्तान के रूप में यह निराशाजनक है। आप जानते हैं, बहुत सी चीज है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं पर वह चीजें नहीं हो रही है। मानसिक तौर पर यह चीजें काफी परेशान करने वाली है। आप यहां जो करने आये है, अगर वह नहीं हो पाता है तो यह एक बड़ी निराशा है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों में कुल 31 रन बनाए हैं। रोहित ने पांच पारियों में सिर्फ 6.20 के

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 2024 के अंतिम दिन 109 अंक फिसला

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में कमजोर रुख के अनुरूप भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार (31 दिसंबर) को साल 2024 के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लाल निशान में बंद हुआ। आईटी स्टॉक्स में गिरावट के बीच अमेरिका में बांड यील्ड में वृद्धि से उभरते हुए शेयर बाजारों पर नेगेटिव असर पड़ा। इसकी वजह से विदेशी निवेशक इन बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स मंगलवार (31 दिसंबर) को 250 से ज्यादा अंक फिसलकर खुला। कारोबार के दौरान यह 1100 से ज्यादा अंक तक फिसल गया था। हालांकि, दिन की बड़ी गिरावट से उबरते हुए सेंसेक्स अंत में 109.12 अंक या 0.14% गिरकर 78,139.01 पर क्लोज हुआ। दूसरी तरफ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 लगभग पिछले बंद भाव पर सपाट रहते हुए 0.10 अंक गिरकर 23,644.80 अंक पर बंद हुआ।

यूनिमेक एयरोस्पेस आईपीओ की बाजार में धमाकेदार एंट्री

नईदिल्ली। इंजिनीरिंग सोल्यूशन कंपनी यूनिमेक एयरोस्पेस एंड मेन्यूफेक्चरिंग लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई। कंपनी के शेयर बीएसई पर 1491 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए, जो प्राइस बैंड 785 रुपये से 90% ज्यादा है। एनएसई पर यूनिमेक एयरोस्पेस आईपीओ के शेयर 1460 रुपये पर लिस्ट हुए। यह भाव इश्यू प्राइस की तुलना में 86% ज्यादा है। यूनिमेक एयरोस्पेस एंड मेन्यूफेक्चरिंग का आईपीओ अप्लाई करने के लिए 23 दिसंबर को खुला था। इश्यू के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 दिसंबर थी। यूनिमेक एयरोस्पेस ने अपने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 745-785 रुपये प्रति शेयर तय किया था। कंपनी ने 5 रुपये प्रति शेयर के फेस वैल्यू पर 63,69,424 शेयरों के फ्रेश इश्यू और 531,84,712 शेयरों की बिक्री पेशकश के जरिये 500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था।

संशोधित और विलंबित आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा बढ़ी

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने भारतीय निवासी व्यक्तियों के लिए संशोधित और विलंबित आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दी है। जिन व्यक्तियों ने समयसीमा पर या उससे पहले आईटीआर दाखिल कर दिया है, वे आवश्यकता पड़ने पर संशोधित दाखिल कर सकते हैं। विलंबित आईटीआर वे लोग दाखिल कर सकते हैं जिन्होंने समयसीमा पर या उससे पहले कोई आईटीआर दाखिल नहीं किया हो और अब आईटीआर दाखिल करना चाहते हों। एकल व्यक्तियों के लिए आईटीआर दाखिल करने की मूल समय सीमा 31 जुलाई, 2024 थी। अगर आपने 31 दिसंबर 2024 तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपको अब लेट फीस से साथ 15 जनवरी 2025 तक फाइल करने का अवसर है। यदि आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1,000 रुपए लेट फीस देनी होगी, और यदि आय 5 लाख से अधिक है तो 5,000 लेट फीस देनी होगी।

दिसंबर में ऑटो बिक्री का धमाका!

नईदिल्ली। 2024 का आखिरी महीना ऑटो सेक्टर के लिए किसी ग्रैंड फिनाले से कम नहीं होने वाला है। कारें, बाइक, ट्रैक्टर- सबके आंकड़े आसमान छूने की तैयारी में हैं। नुवामा इंस्टिट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दिसंबर 2024 में बिक्री का तूफान आने वाला है, और नए साल की शुरुआत ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए धमाकेदार होने वाली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा इस दिसंबर 67,900 गाड़ियां बेचकर 13 प्रतिशत की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करने वाली है, वहीं मारुति सुजुकी (MSIL) भी 1,55,000 यूनिट्स की बिक्री के साथ 13 प्रतिशत की उछाल दिखाएगी। हुंडई 57,000 गाड़ियों की बिक्री कर हल्की-फुल्की 1 प्रतिशत की बढ़त हासिल करेगी, लेकिन टाटा मोटर्स को 6 प्रतिशत की गिरावट का सामना करना पड़ सकता है।

खेल जगत के लिए ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रहा 2024

योगेश कुमार गोयल

2024 का वर्ष खेल जगत के लिए कई मायनों में अद्वितीय, ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रहा। यह वर्ष न केवल नई उपलब्धियों और नए रिकॉर्ड का गवाह बना बल्कि कई युवा खिलाड़ियों के उदय के अलावा खेल में नई तकनीकों के समावेश का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। खेल संस्कृति में बदलाव और तकनीकी उन्नति के कारण खेलों के अनुभव को नई ऊंचाईयां मिली। वर्ष 2024 भारतीय खेलों में क्रिकेट, ओलंपिक, पैरालंपिक, शतरंज ओलंपियाड और फिडे विश्व चैंपियनशिप में सफलता के लिए याद किया जाएगा। भारतीय एथलीटों ने इस वर्ष विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। वॉलीबॉल और टेबल टेनिस जैसे खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। क्रिकेट से लेकर टेनिस, हॉकी, शतरंज के अलावा भारत ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में भी अपना लोहा मनवाया। भारत का इन खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन रहा, जिससे समस्त देशवासी गौरवान्वित हुए। भारत में आयोजित एशियाई खेल और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप ने वैश्विक स्तर पर भारत को एक प्रभावशाली खेल मेजबान के रूप में स्थापित किया। एक क्रिकेट विश्व कप, 6 ओलंपिक पदक, 29 पैरालंपिक पदक और दो शतरंज विश्व चैंपियनशिप सहित 2024 ने भारतीय खेल प्रशंसकों को जश्न मनाने के कई ऐसे अवसर प्रदान किए, जिससे खेलों की दुनिया में भारत का भविष्य उज्जवल नजर आता है।

2024 में खेलों में तकनीकी उन्नति ने निर्णायक भूमिका निभाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और वर्चुअल रियलिटी ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन विश्लेषण को नई दिशा प्रदान की। इसके

अलावा दर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एआर (ऑगमेंटेड रियलिटी) तकनीक का उपयोग किया गया। विश्वनाथन आनंद के बाद इस वर्ष शतरंज के नए चैंपियन उभरकर दुनिया के सामने आए और शतरंज ने खेल प्रेमियों को जश्न मनाने का भरपूर मौका दिया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 45वें चेस ओलंपियाड का आयोजन हुआ था, जिसमें पुरुष वर्ग में 195 देशों की 197 टीमों और महिला वर्ग में 181 देशों की 183 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत की पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने सितंबर में इस ओलंपियाड में पहली बार स्वर्ण पदक जीते, वहीं डी गुकेश और कोनेरू हम्पी ने दिसंबर में विश्व खिताब के साथ नई ऊंचाईयों को छुआ। 12 दिसंबर को सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गुकेश ने महज 18 वर्ष की आयु में पिछली बार के शतरंज चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनकर नया इतिहास रचा। वह विश्वनाथन आनंद के बाद वैश्विक खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बने, वहीं 37 वर्षीया हम्पी ने 28 दिसंबर को अपने कैरियर में दूसरी बार महिलाओं का रैपिड विश्व खिताब जीता।

पिछले साल भारत वनडे विश्व कप 2023 का खिताब जीतने से चूक गया था लेकिन इस वर्ष आईसीसी ट्रॉफी जीतने का 11 वर्ष का सूखा समाप्त करने में भारत सफल हुआ। आखिरी बार महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारत ने 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। रोहित शर्मा की कप्तानी में 30 जून 2024 को भारतीय टीम ने बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को मात देकर टी20 विश्व कप का खिताब जीता। इसी प्रकार भारतीय हॉकी टीम ने पांचवीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत की ओर से जुगराज सिंह ने गोल दागा था, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से मात देते हुए यह खिताब अपने नाम किया। टेनिस में रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में इटली के सिमोन बोलेली और वावसोरी को मात देकर मेंस डबल्स का खिताब जीता और ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बने। उन्होंने 43 वर्ष की उम्र में यह खिताब अपने नाम किया।

शहरों को साफ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाएं : साव

अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के काम में तेजी लाने और उत्कृष्ट निर्माण के निर्देश

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में सभी नगरीय निकायों को अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रियाएं 10 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्रदेशभर के नगरीय निकायों में 353 नए पद मंजूर किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को रोजाना वार्डों का भ्रमण कर निर्माण कार्यों, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों में बन रहे अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के काम में तेजी लाने और इनके उत्कृष्ट निर्माण के निर्देश दिए। साव ने अधिकारियों को गंभीरता और सक्रियता से काम करते हुए राज्य के शहरों को साफ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., विशेष सचिव आर. एक्का और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री साव ने समीक्षा बैठक में सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए अच्छी गुणवत्ता की उत्कृष्ट मूर्ति स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अटल परिसर का इस तरह निर्माण करें कि शहर में इसकी विशेष पहचान और दर्शनीय स्थल बनें। उन्होंने प्रदेश के 12 शहरों में बनाए जा रहे नालंदा परिसर के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र काम प्रारंभ करने को कहा। साव ने अधिकारियों से कहा कि नालंदा परिसर का शानदार और आइकॉनिक निर्माण होना चाहिए। नालंदा परिसर और अटल परिसर का निर्माण सरकार के महत्वाकांक्षी कार्य हैं। उन्होंने आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को खुद इनकी मॉनिटरिंग करने और प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री साव ने बैठक में अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत कार्यों के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत मिशन 2.0, एसटीपी निर्माण और आकांक्षी शौचालयों के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को रोजाना प्रात: भ्रमण कर निर्माण कार्यों, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने 01 जनवरी से ही इसकी शुरूआत कर शहरों में प्रकाश और सफाई की व्यवस्था दुरूस्त करने को कहा। साव ने इसमें किसी भी तरह की कोताही न बरतते हुए गंभीरता और सक्रियता से प्रतिदिन कार्यों की मॉनिटरिंग करने को कहा। इसमें किसी तरह का हीला-हवाला पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

साव ने समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के निर्माणाधीन आवासों को आगामी मार्च महीने तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने गरीबों का आशियाना तैयार करने का काम संवेदनशीलता से करते हुए इनका निर्माण प्राथमिकता से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने किफायती आवास परियोजनाओं के तहत निर्मित आवासों का आबंटन हितग्राहियों को तत्काल करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री साव ने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के दौरान अनिराकृत प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर इन्हें जल्द से जल्द निराकृत करने को कहा।

साव ने नगरीय निकायों में नियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों के समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ऊर्जा की अनावश्यक खपत पर रोक लगाते हुए विद्युत देयकों का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए। लंबित भुगतान के कारण विद्युत देयकों पर सरचार्ज लगने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। साव ने नगरीय निकायों में सेट-अप के पुनरीक्षण के लिए आवश्यक जानकारी संचालनालय को भेजने को कहा। उन्होंने आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सभी कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए।

आगामी शिक्षा सत्र में छात्रों को समय पर मिले पाठ्य पुस्तकें: साय

वितरण की निगरानी 'ऑनलाईन ट्रैकिंग एप' से करने के दिए निर्देश

रायपुर । मुख्यमंत्री साय ने आगामी शिक्षा सत्र में राज्य के समस्त विद्यार्थियों को समय पर नि:शुल्क पुस्तकों का वितरण करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों को समय-सीमा में पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो सकें इसके लिए वितरण कार्य की निगरानी आनलाइन ट्रेकिंग ऐप से की जाए।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को मंत्रालय में आयोजित छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की कार्यकारिणी सभा की 89वीं बैठक में ये निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण हेतु कव्हर पेपर एवं इनर पेपर क्रय एवं अन्य निविदाएं जेम पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश दिये। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, मुख्यमंत्री के सचिव मुकेश बंसल और बसवराजु एस., पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक संजीव कुमार झा भी उपस्थित थे।

पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल की बकाया राशि के भुगतान का ऐतिहासिक निर्णय

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा - कांग्रेस द्वारा पैदा किए गए भरोसे के संकट को खत्म कर शासन और लोकतंत्र के प्रति विश्वास को बहाल करना भाजपा सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरणसिंह देव ने सोमवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों का स्वागत करते हुए कहा है कि कैबिनेट निर्णय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश भाजपा सरकार ने चावल मिलों का पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के कार्यकाल की बकाया राशि के भुगतान का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। श्री देव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को तो ठगा ही था; वादा करने और बाकायदा एग्रीमेंट करने के बावजूद चावल उद्योग की पीठ में छुरा भोंका था। भाजपा सरकार ने पूर्व शासन द्वारा किए एग्रीमेंट का भी

सम्मान किया है। इससे न केवल चावल उद्योग को लाभ मिलेगा, इस उद्योग से जुड़े श्रमिकों से लेकर सभी लाभान्वित होंगे बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी और अधिक मजबूती आएगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि अभी तक 1800 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है। कांग्रेस के समय का 600 करोड़ भी भुगतान हुआ है। यहां यह विशेष तौर पर ध्यान देने की बात है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले दिनों ही दाल-चावल आदि पर मंडी शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। भाजपा सरकार की मंशा यही है कि प्रदेश की खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ होने के साथ-साथ अपना प्रदेश एक्सपर्ट हब बन जाय। हमारे लोग नेशनल/ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में अगली पंक्ति में खड़े दिखें। मंडी शुल्क माफ करने में भी सवाल कांग्रेस के विश्वासघात के विरुद्ध भाजपा के 'विश्वास बहाली' का ही है। श्री देव ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने अपने कथित 'जन घोषणा पत्र' में मंडी शुल्क माफ करने की बात की थी, लेकिन हर बड़े वादे की तरह इसमें भी कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद शुल्क माफ करने की बात तो छोड़िए, उसे बढ़ाकर दुगना कर दिया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसे एक सूत्र वाक्य की तरह इस तरह समझ सकते हैं कि हर विषय में कांग्रेस द्वारा पैदा किए गए भरोसे के संकट को खत्म कर शासन और लोकतंत्र के प्रति विश्वास को बहाल करना भाजपा सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसे इतिहास याद रखेगा।

बी. एड शिक्षकों की सेवाएं यथावत रखने व समायोजन करने की मांगों का

आम आदमी पार्टी का समर्थन -विजय झा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदेश के बीएड प्रशिक्षित युवक युवती लगातार अपनी सेवाओं को निरंतर रखते हुए शिक्षा विभाग में समायोजन की मांग के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड में बस्तर और सरगुजा के बीएड प्रशिक्षित रायपुर पदयात्रा कर धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि महिलाएं अपनी गोदी में छोटी-छोटी बच्चों के साथ यहां आंदोलनरत है। किंतु छत्तीसगढ़ सरकार उनकी मांगों की उपेक्षा कर रही है। आज मंगलवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल साहू के निर्देश पर आंदोलनकारियों के मांगों का तूता धरना स्थल पहुंचकर समर्थन किया। पार्टी के कर्मचारी विंग के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा, रायपुर जिलाध्यक्ष पुनारद निषाद, रायपुर जिला महासचिव रघुराज सिंह ठाकुर, रायपुर जिला कोषाध्यक्ष शिव शर्मा, सहित प्रतिनिधियों ने धरना स्थल पर मांगों का समर्थन किया। आंदोलनकारियों की सभा को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने दावा किया कि नौकरी लगना मुश्किल है, लेकिन एक बार नौकरी लग गया तो नौकरी छूटना महा मुश्किल है। राज्य सरकार किसी भी बीएड प्रशिक्षित शिक्षक को उनकी सेवाओं का सम्मान करें ना कि उनकी सेवाएं समाप्त करें। तूता धरना स्थल में सुविधाओं के अभाव के बीच युवतियां भी दिन भर धरना स्थल में डटे हुए हैं। महिलाओं को किसी प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। श्री झा ने डॉ रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष, अरुण साव उपमुख्यमंत्री एवं आं

ओपी चौधरी वित्त मंत्री को स्मरण कराया की विपक्ष में रहते हुए तूता धरना स्थल का विरोध किया जाता था।

डॉ. सुधाकर थिटे स्मारक प्रथम अंडर-15 सब जूनियर बॉयज लीग फुटबॉल चैंपियनशिप 2024-25 का समापन

लगातार प्रयास ही सफलता की पहली सीढ़ी: बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर। राजधानी रायपुर में आयोजित डॉ. सुधाकर थिटे स्मारक प्रथम अंडर-15 सब जूनियर बॉयज लीग फुटबॉल चैंपियनशिप 2024-25 का सोमवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने विजेता टीमों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया।

समापन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, खेल में हार-जीत लगी रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है खेल भावना और मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। लगातार प्रयास से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि, ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करते हैं और खेल संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। फाइनल मुकाबले में शेरा क्रीड़ा समिति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रह्मविद एफए को 2-1 से हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। शेरा क्रीड़ा समिति की ओर से आदित्येश देब और मयंक गोरे ने 1-1 गोल किए, जबकि ब्रह्मविद एफए की ओर से निहाल सिंह ने एकमात्र गोल किया। तीसरे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में डब्ल्यूआरसी एफसी ने एटीके चैंपियन एफसी को 3-2 से हराया। डब्ल्यूआरसी एफसी के रयान रंगलानी ने 2 और कुणाल कुमार ने 1 गोल किया, जबकि एटीके चैंपियन एफसी की ओर से ऋषभ वर्मा और दोगेश ध्रुव ने 1-1 गोल किए।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया को भी रद्द किया जाये: बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश भर के सभी जिलों में चल रही पुलिस एवं वन आरक्षक भर्ती प्रक्रिया रद्द किया जाये। अभी तक की भर्ती प्रक्रिया की जांच कराई जाये। हैदराबाद की निजी कंपनी जो वन विभाग और पुलिस विभाग में शारीरिक परीक्षा करवा रही

उसको ब्लेक लिस्टेड किया जाये। कंपनी और सरकार में बैठे हुए लोग मिलीभगत कर करके नौकरियां बेच रहे। हैदराबाद की इसी निजी कंपनी को अलग-अलग जिलों में लगभग 6000 आरक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसी सरकार में ही पूर्व में इसी कंपनी ने वन रक्षकों की भर्ती में फिजिकल टेस्ट के इवेंट को कवर किया था, उस पर भी अनेकों सवाल उठे, लेकिन आज तक सरकार ने जांच कराना तक जरूरी नहीं समझा। भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा सत्ता में बैठे बड़े लोगों के संरक्षण के बिना संभव ही नहीं है।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार नौकरियों का व्यापार कर रही है। प्रदेश में वन एवं पुलिस की भर्तियों में बोलियां लग रही। कांग्रेस मांग करती है इन भर्तियो को रोक कर पूरी भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई से अथवा उच्च न्यायालय के जज से जांच करवाई जाये।

प्रदेश की कानून व्यवस्था दिनों दिन बदतर होते जा रही है: शुक्ला

रायपुर। राजधानी में एक बार फिर दो हत्याओं से आम आदमी डरा सहमा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रोज हत्याएं हो रही, चाकू मारे जा रहे, गोलियां चल रही, रायपुर में यह क्या हो

रहा है मुख्यमंत्री जी। अपराधिक तत्व इतने बेखौफ हो गये है कि उनमें पुलिस का भय जरा भी नहीं बचा है। राह चलते किसी को भी चाकू मार दी जा रही, सड़कों पर खुलेआम हत्या हो रही है। प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है राजधानी में सरेआम गोलीबारी की पांच घटनाएं हो चुकी है। सरकार की नाकामी और पुलिस की लापरवाही का परिणाम है कि प्रदेश की राजधानी असुरक्षित हो चुकी है। राजधानी रायपुर चाकूपुर बन गया है। प्रदेश के लगभग सभी शहरों में रोज ही हत्याएं हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं होता भयावह हत्या की एक दो घटनाएं न होती हो, अपराधी इतने बेलगाम हो गये है कि सरेआम सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मार रहे, पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। रोज हो रहे सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं से प्रदेश शर्मसार। पूरे प्रदेश में नागरिकों को भय के माहौल में जीवन जीना पड़ रहा है। साय सरकार के राज में महिलाओं के प्रति अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गयी है।

शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाये: ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार बीएड धारी शिक्षकों को नौकरी से निकालने के बजाय शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति दे। न्यायालय का फैसला डीएड धारी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर है। वैसे

भी प्रदेश में 70000 से अधिक शिक्षकों का पद रिक्त है सरकार ने 33000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा किया था उस दिशा में अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है प्रदेश के बच्चे बिना शिक्षक पढ़ाई कैसे करेंगे?प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले इन 2897 शिक्षकों को समान वेतन पर शिक्षा विभाग में समायोजित करें। बीएड के शिक्षकों को यूडीटी बना दिया जाए बीएड वालों की भर्ती कर ले अदालत के फैसले का सम्मान हो जाएगा इन सब की नौकरी बच जायेगी इनकी भर्ती कांग्रेस सरकार के समय दिसंबर 2023 साथ बीजेपी सरकार आने के बाद फरवरी, मार्च 2024 में हुई थी। 2897 शिक्षक में अधिकांश बस्तर और सरगुजा संभाग के हैं यह दूरस्थ क्षेत्र में पदस्थ हैं इन शिक्षकों में 70 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आते हैं यह उनके भविष्य का सवाल है सरकार उनके मामले में गंभीरता से निर्णय करें।

सत्ता के संरक्षण में साय साय भ्रष्टाचार: वर्मा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा सरकार के कुशासन में पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, अपात्रों पर इस सरकार की विशेष कृपा है। सत्ता के संरक्षण में योजनाओं में बंदरबाट के

अनेकों मामले रोज़ उजागर हो रहे हैं। बिलासपुर जिले में परिवार में पति और बच्चों के साथ रह रही महिला को परित्यक्त पेंशन। अंबिकापुर में 40 साल की अपात्र महिला को वृद्धा पेंशन और महतारी वंदन दोनों। केवल सनी लियोनी ही नहीं महासमुंद जिले के घोड़ारी के सरकारी स्कूल की शिक्षिका को भी मिल रहा महतारी वंदन योजना का लाभ लेकिन लाखों की संख्या में पात्र हितग्राहियों को तरह-तरह के बहाने बनाकर लाभ से वंचित किया गया है।प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि पिछले एक साल के दौरान भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप लगे यह सरकार पारदर्शिता पूर्वक जांच करने के बजाय उन पर पर्देदारी करने में लगी है। लक्ष्मी महिला सहकारी बैंक में महतारी वंदन के लिए खोले गए सैकड़ो खाते में जमा किए गए दस्तावेजों, आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर हितग्राहियों की जानकारी के बगैर उनके नाम से लोन निकाल लिए गए, सैकड़ो महिलाओं के साथ फ्रॉड हुआ।

उपेक्षा देखकर कोई कांग्रेस का सदस्य नहीं बनना चाहता: शर्मा

रायपुर । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा है कि आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लगातार दुर्गति हो रही है, लेकिन बजाय इससे सबक लेने के कांग्रेस के लोग आपसी सिर-फूटौव्वल में लगे हुए हैं। शर्मा ने कहा कि भाजपा

के संगठन महापर्व में छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 60 लाख सदस्य बनाकर इतिहास रचा है और कांग्रेस की दुर्दशा का आलम यह है कि वहाँ कोई सदस्य बनने के लिए जरा भी इच्छुक नहीं है। प्रदेश प्रवक्ता शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के अभाव से जूझ रही कांग्रेस की राजनीतिक दरिद्रता का इससे अधिक परिचय और क्या होगा कि अब कांग्रेस नेतृत्व को पिछले चुनावों के और निष्कासित नेताओं से आवेदन मंगवाना पड़ा है! कांग्रेस के इसी राजनीतिक चरित्र के कारण एक तरफ जहाँ सम्मेलनों में बड़े नेताओं को कार्यकर्ता मुँह पर खूब खरी-खोटी सुनाने में नहीं हिचक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और अपमान को देखकर कोई भी कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं है। शर्मा ने कहा कि भाजपा की ऐतिहासिक सदस्य संख्या भाजपा के प्रति अटूट जन-विश्वास का प्रमाण पत्र है। भाजपा विश्व की एकमात्र सबसे बड़ी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है।

24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन

तीरंदाज़ी में पूर्वी उत्तरप्रदेश का जलवा, 12 में से चार पदक जीते

रायपुर । राजधानी रायपुर में चल रहीं 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। समापन समारोह के दौरान फुटबॉल के फाइनल मैच में संथाल परगना ने केरल को पेनाल्टी शूट में एक के मुकाबले चार गोलों से हराकर चैंपियन की ट्रॉफी जीती। केरल की टीम उपविजेता रहीं वहीं झारखण्ड की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। तीरंदाजी की प्रतियोगिता में पूर्वी उत्तर प्रदेश के बालक तीरंदाज और कर्नाटक की बालिकाएं छायी रहीं। इस पूरी प्रतियोगिता में फुटबॉल और तीरंदाजी के खेलों में लगभग 600 जनजातीय बालक-बालिकाओं ने हिस्सा लिया। अण्डमान, निकोबार से लेकर पूरे देश के लगभग 30 प्रांतों से जनजातीय खिलाड़ी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए। पड़ोसी देश नेपाल से भी खिलाड़ियों के एक दल ने तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री एवं स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री केदार कश्यप और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कोटा स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और बेहतरीन खेल दिखाने के लिए सभी का हौसला बढ़ाया। समापन समारोह में अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम

के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्येन्द्र सिंह, अखिल भारतीय खेल-कूद प्रमुख श्री फूल सिंह लेप्चा, राष्ट्रीय महामंत्री योगेश बापट, छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष श्री उमेश कच्छप और संगठन मंत्री श्री रामनाथ कश्यप, सचिव श्री अनुराग जैन और स्वागत समिति के सचिव श्री अमर बंसल, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री प्रवीण ढोलके, सह संगठन मंत्री श्री सुभाष बडोले, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग प्रमुख प्रोफेसर राजीव चौधरी, वनवासी विकास समिति महानगर रायपुर के अध्यक्ष श्री रवि गोयल और सचिव श्री राजीव शर्मा सहित सह खेल-कूद प्रमुख श्री पंकज सिंह, श्रीमती संगीता चौबे, डॉ. विजय साण्डिल्य, डॉ. आशुतोष साण्डिल्य, डॉ. मीना मूर्मू, श्री टिशेन भगत श्री गोपाल वियानी भी उपस्थित रहे।

संभवत: जनजातीय खिलाड़ियों की यह विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता - अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित इस 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री अतुल जोग ने कहा कि यह प्रतियोगिता 1991 से अनवरत आयोजित होती आ रहीं है और यह प्रतियोगिता विशुद्ध रूप से जनजातीय खिलाड़ियों की सहभागिता वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है।

150 युवाओं और महिलाओं को मिला रोजगार

रायपुर। राजनांदगांव जिले के बंद पड़ी खदानों को आजीविका के लिए उपयोगी बनाते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केज कल्चर तकनीक से मछली पालन का कार्य तेजी से लोकप्रिय और फायदेमंद साबित हो रहा है। यह नवाचार न केवल मत्स्य पालकों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हुआ है, बल्कि 150 से अधिक स्थानीय बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार का नया जरिया भी बन गया है।

जिले के ग्राम जोरातराई में बंद पड़ी खदानों को जलस्रोत के रूप में उपयोग करते हुए 9.72 करोड़ रुपए की लागत से 18 इकाइयों में कुल 324 केज लगाए गए हैं। प्रत्येक केज इकाई की लागत 3 लाख रुपए है, जिसमें से 60 प्रतिशत अनुदान के रूप में 5.83 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। केज कल्चर, जिसे नेट पेन कल्चर भी कहा जाता है, जलाशय में फ्लोटिंग केज यूनिट स्थापित करने की एक आधुनिक तकनीक है। इसमें एक केज यूनिट में चार बाड़े होते हैं, जहां उंगली के आकार की मछलियों को पाला जाता है, जो पांच माह में लगभग एक से सवा किलो वजन की हो जाती है। इस

तकनीक में तिलापिया और पंगेसियस जैसी मछलियों का पालन किया जा रहा है। प्रत्येक केज से 2.5 से 3 टन तक मछली उत्पादन होता है, जिससे 6 से 8 हजार रुपए की मासिक आमदनी होती है।

ग्राम मुढ़ीपार स्टेशन पारा की श्रीमती पूर्णिमा साहू ने बताया कि जय मां संतोष महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से केज कल्चर तकनीक से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। समूह की महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार प्रकट किया है। जोरातराई की खदानों में 8 लाख से अधिक मछलियां पाली जा रही हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.